https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'यह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृति अमर रहेगी'

वर्ष-13, अंक-24 16-31 दिसंबर, 2018 (पाक्षिक) ₹20

नए भारत की ओर...

ग्रामीण भारतः यूपीए और एनडीए सरकारों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन

अटलजी : सौहार्द के महान् दूत और नेता

लोकतंत्र का गला घोंट रही है ममता सरकार : अमित शाह

नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में दैनिक जागरण के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

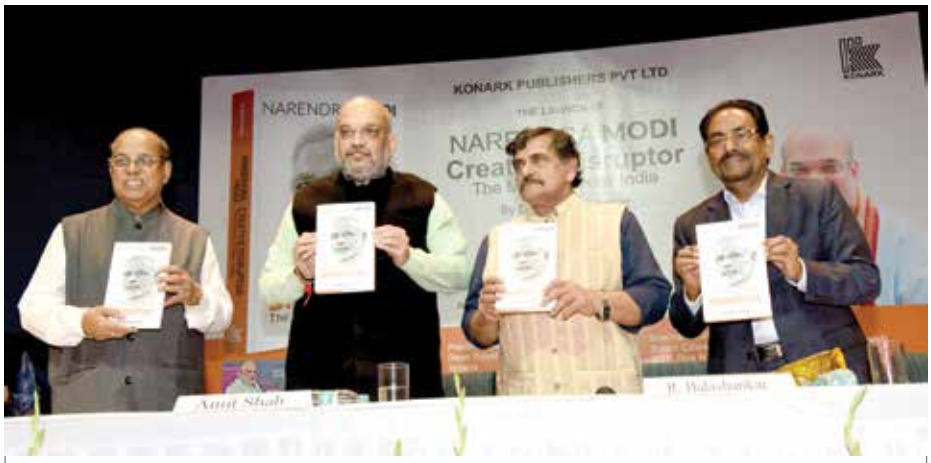

06 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच साल में अर्थव्यवस्था को छठे स्थान पर मजबूती से स्थापित किया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, "एक चायवाला" ने अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह, एक प्रख्यात "अर्थशास्त्री" की तुलना में अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में बेहतर काम किया है।...

वैचारिकी

राष्ट्र के वैभव में व्यक्ति का वैभव 13

श्रद्धांजलि

'महामना' पंडित मदन मोहन मालवीय 15

लेख

अटलजीः सौहार्द के महान् दूत और नेता 16

ग्रामीण भारतः यूपीए और एनडीए सरकारों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन 18

अन्य

एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) निकासी 100 प्रतिशत कर मुक्त 11

जी-20 शिखर सम्मेलन, ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) 20

पीएसएलवी-सी43 ने उपग्रह एचवाईएसआईएस और 30 विदेशी... 22

बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को फिर से अपना पूरा समर्थन देते हैंः ब्रिक्स 23

ब्रिटेन की अदालत द्वारा विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश 24

'भारत के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है नीली अर्थव्यवस्था' 25

सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन जारी 26

2017-18 में 28.48 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ 28

लोकतंत्र का गला घोंट रही है ममता सरकार : अमित शाह 29

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिये क्रिश्चियन... 31

यह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृति अमर रहेगीः नरेंद्र मोदी 32

राफेल सौदे में नहीं मिला अनियमितता का कोई सबूतः उच्चतम न्यायालय 33

07 भाजपा राष्ट्रीय परिषद् का अधिवेशन 11-12 जनवरी को दिल्ली में

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेन्द्र यादव ने 13 दिसंबर को पार्टी के...

08 जनादेश विनम्रता से स्वीकारः नरेन्द्र मोदी

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया तथा...

10 चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19...

12 केन्द्र से पिछले चार वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को 3200 करोड़ रुपये की मदद मिली

पिछले चार वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्र की ओर से 3200 करोड़ रुपये की मदद दी गई। केंद्रीय...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

70 साल में पहली बार हमारी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के बारे में सोचा है। हम बहुत ईमानदारी और परिश्रम से किसानों को खेती से जुड़े संकटों से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

@AmitShah

देश की जनता के सामने दो विकल्प हैं, एक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार जो भ्रष्टाचार विहीन शासन देकर देश के सम्मान को विश्व में सबसे ऊपर ले जाये और दूसरा महागठबंधन वाली एक मजबूर सरकार जिसकी मजबूरी के पीछे ये सारी पार्टियां मिलकर भ्रष्टाचार करें।

@Ramlal

1984 के सिख दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट करते हुए उसके नेता सज्जन कुमार को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई। स्वागत योग्य निर्णय। अब कांग्रेस को इस भयानक नरसंहार के लिए सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए।

facebook

किसानों के अथक परिश्रम की बदौलत ही आज हरियाणा राज्य कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है। प्रदेश का मेहनतकश किसान जहां देश के लोगों का पेट भरने में अपना अहम योगदान देता है, वहीं उसका अन्न के निर्यात में भी अहम योगदान है। — **मनोहर लाल**

किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं से प्रोत्साहित प्रदेश के किसान ने खाद्यान्न उत्पादन में ऊंची छलांग लगाकर राज्य को देश में प्रथम स्थान दिलाया। आधुनिक तकनीक, आवश्यक कृषि निवेश तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर प्रदेश का किसान देश ही नहीं, पूरी दुनिया का पेट भरने हेतु पर्याप्त अन्न उत्पन्न करने में सक्षम है। — **योगी आदित्यदनाथ**

एनडीए सरकार ने चार साल में 7 आइआइटी, 7 आइआइएम, 14 आइआइटी, 1 एनआइटी, 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालय स्थापित किए। बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट और बीआईटी मेसरा के पटना कैम्प्स भी एनडीए शासन की देन हैं। — **सुशील कुमार मोदी**

भाजपा राष्ट्र के प्रति समर्पित

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विनम्रता से स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा को सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति तथा मिजो नेशनल फ्रंट को चुनावों में अनुकूल परिणामों के लिए भी बधाई दी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की भी चुनावों में दिन–रात अथक मेहनत के लिये प्रशंसा की है। उन्होंने आने वाले दिनों में और अधिक कड़ी मेहनत से देश में चल रहे विकास कार्यों की और मजबूत करने का भी आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है। कार्यकर्ता ही भाजपा संगठन की रीढ़ है। भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसका आधार असंख्य कार्यकर्ताओं का त्याग एवं समर्पण है। पार्टी का एक–एक कार्यकर्ता विचारधारा को समर्पित है और मां भारती की सेवा में दिन–रात लगा है। जहां पार्टी सिद्धांतनिष्ठ राजनीति में विश्वास करती है, इसके कार्यकर्ता के मन–मस्तिष्क में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहता है। कभी–कभी सिद्धांतनिष्ठ राजनीति चुनावी शोर–शराबे में डूब जाती है, परन्तु अंततः सिद्धांतों की ही विजय होती है। भाजपा की दृष्टि राष्ट्रीय हित की दृष्टि है और यही कारण है कि तात्कालिक चुनावी लाभ के लिए यह वोट–बैंक की राजनीति नहीं करती। यही भाजपा की शक्ति रही है और मूल्य आधारित राजनीति के बल पर हमारे कार्यकर्ताओं ने विषम से विषम परिस्थितियों में भी पार्टी के लिए राह बनाई है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मिश्रित परिणाम रहे। जहां कांग्रेस को मिजोरम में सत्ता से हाथ धोना पड़ा, वहीं तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के सामने कांग्रेस–तेलुगू देशम पार्टी गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिली, परन्तु मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस के संतोष करने लायक कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि भाजपा के पंद्रह वर्षों के शासन के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने पक्ष में कोई लहर खड़ी नहीं कर पाई। वोटों की गिनती के दौरान कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी की भी जीत हो सकती है और अंततः कांग्रेस भी बहुमत से कुछ कदम दूर ही रही। वोट प्रतिशत के मामले में भी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में दोनों दल काफी नजदीक रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे हावी रहे, जिनका असर इन प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर पड़ा। इन प्रदेशों ने भाजपा शासन में विकास के नये मानदण्डों को गढ़ा है और अब विपक्ष में रहते हुए भाजपा नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सुशासन एवं विकास की राह से यहां की सरकारें भटके नहीं।

विधान सभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे हावी रहे, जिनका असर इन प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर पड़ा। इन प्रदेशों ने भाजपा शासन में विकास के नये मानदण्डों को गढ़ा है और अब विपक्ष में रहते हुए भाजपा नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सुशासन एवं विकास की राह से यहां की सरकारें भटके नहीं।

राष्ट्र के समक्ष अनेक कठिन चुनौतियां एवं अवसर हैं। 2014 के आम चुनावों में देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को भारी जनादेश दिया था। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि देश की विकास दर गिर रही थी, पॉलिसी पैरेलिसिस एवं कुशासन के साथ–साथ अनगिनत घपलों–घोटालों एवं भ्रष्टाचार से देश त्रस्त था। पूरे वातावरण में नकारात्मकता थी एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक निराशाजनक वातावरण बन गया था। इन परिस्थितियों में देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना। श्री नरेन्द्र मोदी न केवल देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए, बल्कि उन्होंने हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। सुशासन एवं विकास के लगभग हर मानदंड पर भारत की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है और पूरी दुनिया अब भारत का लोहा मान रही है। भारत आज विश्व की सबसे तेज विकास दर वाले देश के साथ–साथ विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। केवल पांच वर्षों में नौवीं से छठी अर्थव्यवस्था की छलांग लगाकर भारत अब पूरे विश्व की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं का केन्द्र बन चुका है। गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला एवं युवाओं के लिए अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। सरकार के कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचाने के लिये भाजपा कार्यकर्ता दिन–रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज जब देश व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, विपक्ष झूठे प्रोपेगेंडा करके अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहता है। यह समय है कि भाजपा कार्यकर्ता आत्मविश्वास के साथ जनसेवा में समर्पित भाव से जुड़े रहें। केवल ईमानदार एवं समर्पित कार्य ही विपक्ष के झूठे प्रोपेगेंडा का सही जवाब हो सकता है। भाजपा के एक–एक कार्यकर्ता को मां भारती की सेवा में और अधिक दृढ़ता से जुटे रहना होगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

'नरेन्द्र मोदी क्रिएटिव डिसरप्टर: द मेकर ऑफ न्यू इंडिया' का लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच साल में अर्थव्यवस्था को छठे स्थान पर मजबूती से स्थापित किया

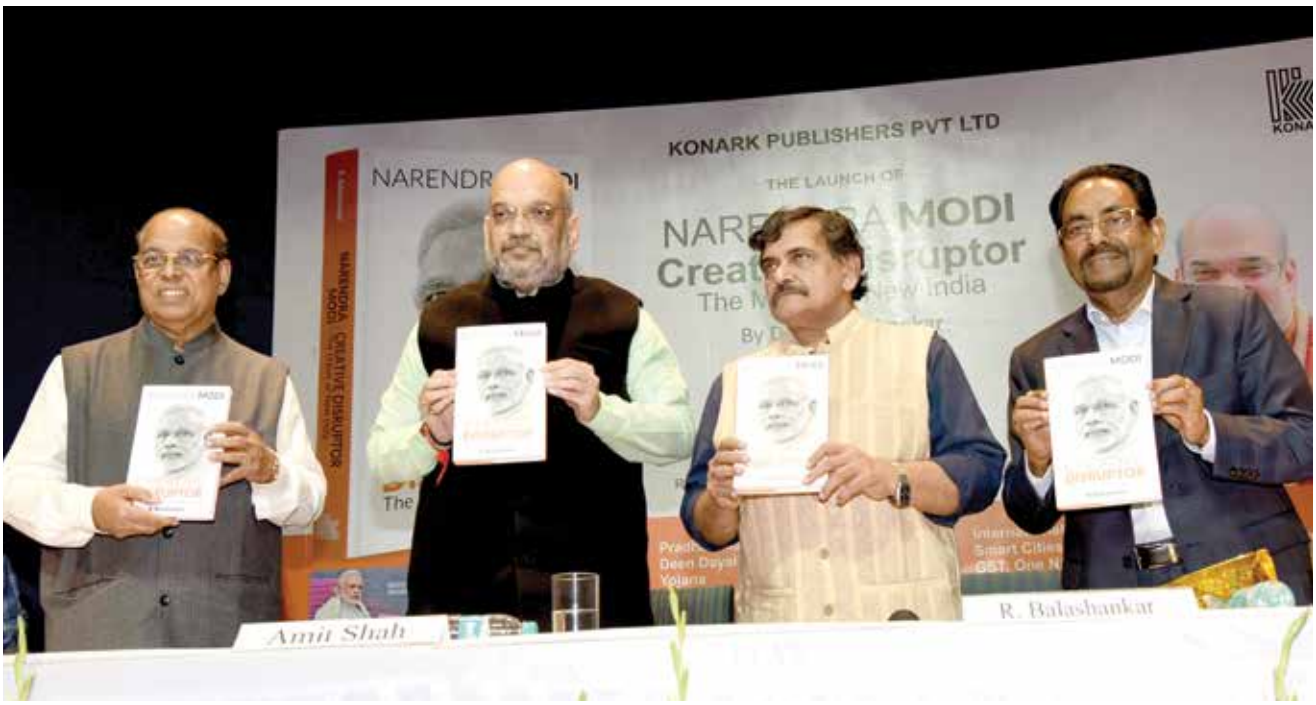

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, "एक चायवाला" ने अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह, एक प्रख्यात "अर्थशास्त्री" की तुलना में अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में बेहतर काम किया है।

गत 10 दिसंबर, 2018 को तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में एक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सफल रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक "नरेंद्र मोदी क्रिएटिव डिसरप्टरः द मेकर ऑफ न्यू इंडिया" के लेखक आर. बालाशंकर है। यह पुस्तक जीएसटी, नोटबंदी, राफेल, मॉब लिंचिंग, असहिष्णुता और कई अन्य विषयों को लेकर मोदी सरकार की आलोचनाओं का ठोस जवाब देती है। विदित हो कि श्री बालाशंकर 'ऑरगेनाइजर' साप्ताहिक के संपादक रहे हैं एवं वर्तमान में भाजपा पत्रिकाएं एवं प्रकाशन विभाग के सदस्य हैं।

श्री अमित शाह ने कहा, "मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को नौवें स्थान पर पहुंचा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले पांच साल में अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए इसे पुनः छठे स्थान पर स्थापित किया और आने वाले छह महीनों में ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हमें आपके असीम ज्ञान से कोई समस्या नहीं है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह भी मानना होगा कि एक चायवाला देश को आपसे बेहतर संभाल रहा है।"

श्री शाह ने कहा, "कोई भी व्यक्ति जो अपने फैसलों पर अटल रहे और पूरी शक्ति के साथ काम करता हो, उसे स्वेच्छाचारी कहना गलत होगा। हमारी राजनीति में ऐसे लोग भी रहे हैं जो 16 साल, 17 साल के लिए प्रधानमंत्री बनी। ऐसी सरकारें भी रहीं, जिन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान केवल 4-5 निर्णय ही ऐसे थे जिन्हें ऐतिहासिक कहा जा सकता था। यह सरकार केवल पांच वर्षों के लिए रही है और मैं 30 निर्णयों की सूची दे सकता हूं जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई है इनमें भी प्रमुख सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी और विमुद्रीकरण है।" ■

भाजपा राष्ट्रीय परिषद् का अधिवेशन 11-12 जनवरी को दिल्ली में

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेन्द्र यादव ने 13 दिसंबर को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

श्री यादव ने कहा कि आज पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश अध्यक्षों एवं प्रदेश संगठन महामंत्रियों की पूर्व निर्धारित बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 2019 में होने वाले लोक सभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय परिषद् एवं पार्टी के अन्य मोर्चों के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने किया।

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि 11-12 जनवरी, 2019 को इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् का अधिवेशन होगा जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं समस्त जन-प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

श्री यादव ने कहा कि 2019 के आम चुनाव की तैयारी के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में पार्टी के विचारों एवं नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के सभी मोर्चे सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक दृष्टि से सात मोर्चे हैं। देश के युवाओं को लोक सभा चुनावों के लिए पार्टी की गतिविधियों से अवगत कराने एवं योजनायें बनाने के लिए 15-16 दिसंबर, 2018 को सिविक सेंटर दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि 21-22 दिसंबर, 2018 को अडलज, अहमदाबाद (गुजरात) में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन आहूत किया गया है। इस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पार्टी की जन-प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ केन्द्रीय नेता भाग लेंगी। 22 दिसंबर को अदलज में भी महिलाओं की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की जायेगी जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी संबोधित करेंगे।

श्री यादव ने कहा कि 19-20 जनवरी, 2019 को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाएगा जिसमें जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी पदाधिकारी भाग लेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, वरिष्ठ नेता श्री थावरचंद गहलोत भी बैठक को संबोधित करेंगे। 20 जनवरी, 2019 को नागपुर में एक विशाल सभा का भी आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजित 31 जनवरी - 01 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में किया जाएगा जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह संबोधित करेंगे।

श्री यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 02-03 फरवरी, 2019 को भुबनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित की जायेगी। इसमें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पार्टी के पिछड़े वर्ग मोर्चा (ओबीसी मोर्चा) का राष्ट्रीय अधिवेशन 15-16 फरवरी, 2019 को पटना (बिहार) में आहूत की गई है। 16 फरवरी 2019 को पटना के गांधी मैदान में ओबीसी वर्ग की एक बहुत बड़ी सभा भी आयोजित की जायेगी। इस सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास भी संबोधित करेंगे।

श्री यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन 21-22 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसान मोर्चे की बैठक को संबोधित करेंगे।

श्री यादव ने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इन मोर्चों की बैठक में जायेंगे और 2019 के आम सभा चुनाव के दृष्टिकोण से योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। ■

भाजयुमो कार्यशाला	15-16 दिसंबर, 2018
महिला मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन	21-22 दिसंबर, 2018
भाजपा राष्ट्रीय परिषद् अधिवेशन	11-12 जनवरी, 2019
अनु. जाति मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन	19-20 जनवरी, 2019
अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी	31 जनवरी-1 फरवरी, 2019
अनु. जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी	2-3 फरवरी, 2019
ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन	15-16 फरवरी, 2019
किसान मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन	21-22 फरवरी, 2019

जनादेश विनम्रता से स्वीकार: नरेन्द्र मोदी

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में वह बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सत्ता में दोबारा वापसी कर ली। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस से राज्य की सत्ता छीन ली।

मध्य प्रदेश : 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं भाजपा को 109 सीटें मिलीं। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दो सीट दूर रह गई। वहीं 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी, 1 समाजवादी पार्टी और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में गईं। मत प्रतिशत की तस्वीर मध्य प्रदेश में बहुत दिलचस्प रही। कांग्रेस को 40.9 फीसदी मत मिले। वहीं, भाजपा का मत प्रतिशत 41 फीसदी रहा। यानी कांग्रेस का वोट प्रतिशत भाजपा से कम रहा, इसके बावजूद कांग्रेस अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही। बसपा का वोट प्रतिशत इस बार गिरकर पांच फीसदी रह गया जबकि निर्दलियों का मत प्रतिशत मामूली रूप से बढ़कर 5.8 हो गया।

राजस्थान : राजस्थान में हर पांच वर्ष में सत्ता परिवर्तन की परंपरा बरकरार रही। राजस्थान में कांग्रेस ने 99 सीटों और भाजपा ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की। बहुजन समाज पार्टी ने 6, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3, माकपा ने 2, भारतीय ट्रायबल पार्टी ने 2, राष्ट्रीय लोकदल ने 1 एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने 13 स्थानों पर जीत हासिल की। भाजपा को 38.8 प्रतिशत मत मिले और कांग्रेस को 39.3 फीसदी। निर्दलियों को इस बार 9.5 प्रतिशत वोट मिला। इसी के साथ उन्होंने अधिक सीटें भी हासिल की।

छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत दर्ज कर अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। भाजपा को 15 सीटें मिलीं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) को 5 और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिलीं। छत्तीसगढ़ में देखें तो, कांग्रेस को इस चुनाव में 43 फीसदी और भाजपा को 33 फीसदी मत मिले।

तेलंगाना : तेलंगाना विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 88, कांग्रेस ने 19, एआइएमआइएम ने 7, तेलगू देशम ने 2, भारतीय जनता पार्टी ने 1 एवं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1 सीट पर जीत हासिल की वहीं 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तेलंगाना में टीआरएस सत्ता में बड़े जनादेश के साथ लौटी। इसके वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई। 2014 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति को करीब 34 फीसदी वोट मिले थे, वहीं इस बार इसे 46.9 प्रतिशत मत हासिल हुए। कांग्रेस को 28.4 फीसदी मत मिले। तेदेपा की बुरी तरह से पराजय हुई। भाजपा का मत करीब सात प्रतिशत पर बरकरार रहा।

मिजोरम : मिजोरम एक मात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को सत्ता और वोट प्रतिशत, दोनों का नुकसान हुआ और भाजपा को बढ़त मिली। 40 सदस्यीय विधानसभा में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने 26 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। 10 साल बाद एमएनएफ ने सत्ता में वापसी की। कांग्रेस ने 5, भाजपा ने 1 एवं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 2013 के विधानसभा चुनाव में करीब 45 फीसदी मत मिले थे जो 2018 में गिरकर 30.2 प्रतिशत रह गए, जबकि भाजपा का मत प्रतिशत 0.4 से बढ़कर आठ फीसदी हो गया। एमएनएफ का मत प्रतिशत 28.8 से बढ़कर 37.6 हो गया है। ■

'जीत-हार जीवन का हिस्सा हैं'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों में जीत पर कांग्रेस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनादेश को विनम्रता के साथ स्वीकार करती है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट कर तेलंगाना में जीत के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री के सी राव को भी बधाई दी। उन्होंने मिजोरम में विजय के लिए मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) को भी बधाई दी।

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने रात-दिन मेहनत की और वह उन्हें सलाम करते हैं। श्री मोदी ने कहा, "जीत-हार जीवन का हिस्सा हैं। आज का परिणाम लोगों की सेवा और भारत के विकास के लिए और कठिन मेहनत करने के हमारे संकल्प को अधिक मजबूत बनाएगा।"

उन्होंने ट्वीट किया, "जीत के लिए कांग्रेस को बधाई। तेलंगाना में भारी जीत के लिए केसीआर गारु और मिजोरम में विजय के लिए मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) को बधाई।"

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भाजपा को मौका देने के लिए धन्यवाद दिया।

श्री मोदी ने कहा, "इन राज्यों में भाजपा की सरकारों ने लोगों के कल्याण के लिए बिना रूके काम किया।"

मध्य प्रदेश	
दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	114
बहुजन समाज पार्टी	2
भारतीय जनता पार्टी	109
समाजवादी पार्टी	1
निर्दलीय	4
कुल	230

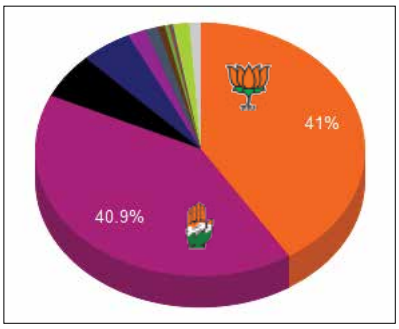

राजस्थान	
दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	99
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	2
बहुजन समाज पार्टी	6
भारतीय जनता पार्टी	73
भारतीय ट्रायबल पार्टी	2
राष्ट्रीय लोक दल	1
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	3
निर्दलीय	13
कुल	199

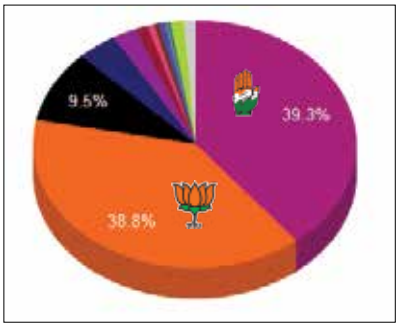

छत्तीसगढ़	
दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	68
बहुजन समाज पार्टी	2
भारतीय जनता पार्टी	15
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	5
कुल	90

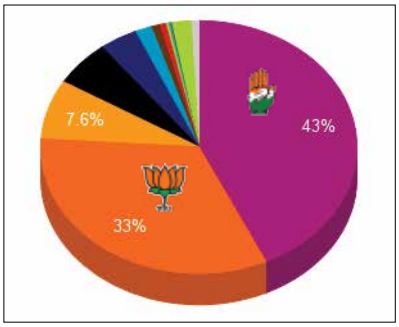

तेलंगाना	
दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	19
भारतीय जनता पार्टी	1
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	7
तेलुगु देशम	2
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति	88
ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक	1
निर्दलीय	1
कुल	119

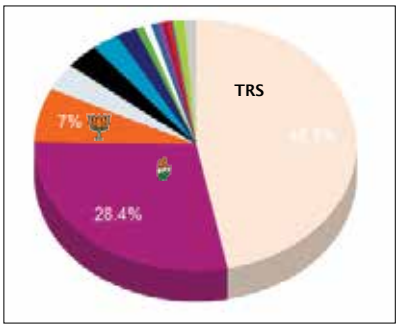

मिजोरम	
दल का नाम	विजयी
इंडियन नेशनल कांग्रेस	5
भारतीय जनता पार्टी	1
मिजो नेशनल फ्रंट	26
निर्दलीय	8
कुल	40

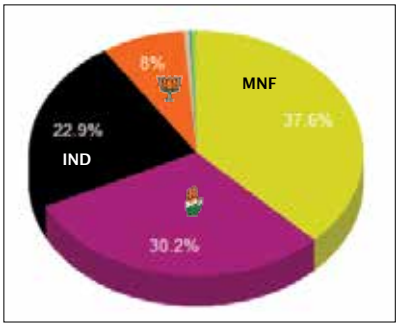

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही। अर्थव्यवस्था में निवेश की रफ्तार बढ़ी है और कृषि तथा मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन भी पिछले साल की अपेक्षा बेहतर हुआ है।

जिन क्षेत्रों ने वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में 7.0 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज की है उनमें 'विनिर्माण', 'विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं', 'निर्माण' एवं 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं' शामिल हैं। 'कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन', 'खनन एवं उत्खनन', 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाओं' और 'वित्तीय, अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाओं' की वृद्धि दर क्रमशः 3.8, (-) 2.4, 6.8 और 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बढ़कर 33.98 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह 31.72 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। यह स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में बुनियादी स्थिर मूल्यों (2011-12) पर तिमाही जीवीए (सकल मूल्य वर्द्धित) के बढ़कर 31.40 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 29.38 लाख करोड़ रुपये था। यह 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।

कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन

वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में बुनियादी मूल्यों पर 'कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन' सेक्टर की तिमाही जीवीए वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत थी। कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण एवं विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के खरीफ सीजन के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2017-18 की समान अवधि में यह दर 1.7 प्रतिशत आंकी गई थी।

खनन एवं उत्खनन

वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में बुनियादी मूल्यों पर 'खनन एवं उत्खनन' सेक्टर की तिमाही जीवीए वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत घट गई, जबकि वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत दर्ज की गई थी। खनन क्षेत्र के महत्वपूर्ण संकेतकों यथा कोयला, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन और आईआईपी से जुड़े खनन की वृद्धि दर वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में क्रमशः

6.2, (-)4.4, (-)2.0 तथा 1.0 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में ये दरें क्रमशः 8.5, (-)0.7, 4.7 तथा 7.1 प्रतिशत आंकी गई थीं।

विनिर्माण

वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में बुनियादी मूल्यों पर 'विनिर्माण' सेक्टर की तिमाही जीवीए वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत आंकी गई, जबकि वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत थी। आईआईपी से जुड़े विनिर्माण ने वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह दर 2.5 प्रतिशत आंकी गई थी। ■

एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) निकासी 100 प्रतिशत कर मुक्त

केन्द्र सरकार का योगदान बढ़कर 14 प्रतिशत हुआ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसम्बर की बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसके एक अहम् फैसले में निर्णय लिया गया कि एनपीएस से बाहर निकलने पर मिलने वाली समूची निकासी राशि अब आयकर से मुक्त होगी। यही नहीं, केन्द्र सरकार ने एनपीएस टियर-। के दायरे में आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए अपना अनिवार्य अंशदान मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य फैसले निम्न हैं:

- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंडों और निवेश के स्वरूप के चयन की आजादी दी गई है।
- वर्ष 2004-2012 के दौरान एनपीएस में अंशदान न करने या इसमें विलम्ब होने पर क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- एनपीएस के टियर-।। के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाला अंशदान अब आयकर की दृष्टि से 1.50 लाख रुपये तक की छूट के लिए धारा 80 सी के अंतर्गत कवर होगा। यह अन्य योजनाओं जैसे कि सामान्य भविष्य निधि, अंशकारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि के सम्तुलय है, बशर्ते कि इसमें तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि हो।

प्रमुख प्रभाव

- एनपीएस के दायरे में आने वाले केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की अंतिम संचित राशि में वृद्धि होगी।
- कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े बगैर ही सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ जायेगी।
- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंडों और निवेश के स्वरूप या रूपरेखा के चयन में आजादी मिलेगी।
- एनपीएस के दायरे में आने वाले केन्द्र सरकार के लगभग 18 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
- जीवन प्रत्याशा बढ़ने की स्थिति में वृद्धावस्था सुरक्षा बढ़ जायेगी।
- एनपीएस को और ज्यादा आकर्षक बनाने से सरकार को सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने एवं उन्हें सेवा में बनाये रखने में आसानी होगी।

निहित व्यय

इस वजह से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोष पर लगभग 2840 करोड़ रुपये का भार पड़ने का अनुमान है और यह एक आवर्ती व्यय के रूप में होगा। वर्ष 2004-2012 के दौरान एनपीएस में अंशदान न करने या इसमें विलम्ब होने पर क्षतिपूर्ति किये जाने के प्रावधान के कारण जो वित्तीय भार पड़ेगा वह इस राशि के अतिरिक्त होगा।

लाभार्थियों की संख्या

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने से एनपीएस के दायरे में आने वाले केन्द्र सरकार के लगभग 18 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
- दायरे में आने वाले राज्य/जिले
- समस्त भारत
- पहले से ही कार्यान्वित की जा रही योजना, यदि कोई हो, का विवरण एवं प्रगति
- फिलहाल यह स्थिति है कि 1 जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद केन्द्र सरकार की सेवा से जुड़ने वाले नये कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किया जाता है। देश में एनपीएस का कार्यान्वयन और नियमन पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

1 जनवरी, 2004 को अथवा उसके बाद केन्द्र सरकार की सेवा से जुड़ने वाले नये कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने वर्ष 2015 में अपने विचार विमर्श के दौरान एनपीएस से जुड़ी विशिष्ट चिंताओं पर गौर किया और सिफारिशें पेश कीं।

7वें वेतन आयोग ने इस संबंध में सचिवों की एक समिति गठित करने की सिफारिश की। तदनुसार, सरकार द्वारा वर्ष 2016 में सचिवों की एक समिति गठित की गई जिसे एनपीएस के कार्यान्वयन को युक्तिसंगत अथवा सरल बनाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। समिति ने वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट पेश की। तदनुसार, समिति की सिफारिशों के आधार पर मसौदा कैबिनेट नोट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के विचारार्थ पेश किया गया। ■

केन्द्र से पिछले चार वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को 3200 करोड़ रुपये की मदद मिली

पिछले चार वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्र की ओर से 3200 करोड़ रुपये की मदद दी गई। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप पुरी ने 1 दिसंबर को पूर्वोत्तर राज्यों में अर्बन मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा के अवसर पर बताया कि इन चार वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई अर्बन) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए 2.3 लाख मकान बनाए जाने को मंजूरी दी गई। इनमें से 1.16 लाख मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मकानों के निर्माण के लिए सिक्किम की सौ फीसदी मांग मंजूर कर ली गई है।

उन्होंने कहा कि मकानों के निर्माण के लिए दी गई इन मंजूरियों को 2004 से 2014 की दस वर्ष की अवधि के दौरान जवाहर लाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन तथा राजीव आवास योजना के तहत 26041 मकानों के निर्माण के लिए दी गई मंजूरी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2004-14 के दौरान जितने मकानों के लिए मंजूरी दी गई थी, उनमें से अभी तक 21159 मकान बने बाकी के 4892 मकान अभी भी निर्माणाधीन हैं।

श्री पुरी ने कहा कि पिछले चार वर्षों की अवधि में पूर्वोत्तर राज्यों को पीएमएवाई अर्बन योजना के तहत 3570 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद मंजूर की गई और 1520 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि 2004-14 की अवधि में 683 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे और 586 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख से लेकर 2.67 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है।

स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा में बताया गया कि इसके लिए पूर्वोत्तर के 10 शहरों का चयन किया गया है और मिशन के तहत अब तक केंद्र की ओर से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1024 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। सिक्किम के नामची शहर में सबसे ज्यादा प्रगति का उल्लेख किया गया है। स्मार्ट शहरों में सभी तरह ही जन सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए क्लाउड आधारित आईसीसीसी प्रणाली विकसित करने के लिए बीईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और नगालैंड को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित कर दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के 98 शहरों को यह दर्जा हासिल हुआ है। 47000 घरों में शौचालय बनाए गए हैं तथा 2310 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। जनवरी 2019 तक समूचे पूर्वोत्तर राज्यों को खुले में शौच मुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।

रीयलटी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लाए गए रेरा कानून को असम और त्रिपुरा में अधिसूचित कर दिया गया है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में अंतरिम स्तर पर रेरा प्राधिकरणों का गठन किया गया है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों में रेरा कानून जल्द ही लागू हो जाएंगे। ■

मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और नगालैंड खुले में शौच से मुक्त

- मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और नगालैंड ने खुले में शौच से मुक्त राज्य का दर्जा हासिल किया
- सिक्किम ने निजी घरेलू शौचालय निर्माण का 67 प्रतिशत और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण का 79 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया
- सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ने घरों से कचरा संग्रहण का सौ फीसदी लक्ष्य हासिल किया
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्र की ओर से 1024 करोड़ रुपए जारी किए गए
- 100 स्मार्ट शहरों में से 10 पूर्वोत्तर के शहर चिन्हित किए गए।
- इम्फाल, ईटानगर, पासीघाट, नामची, गंगटोक और शिलांग में क्लाउड आधारित आईसीसीसी प्रणाली विकसित करने के लिए बीईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2.3 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी
- अब तक 1.16 लाख मकानों का निर्माण शुरू, मकानों के निर्माण के लिए त्रिपुरा की मांग सौ फीसदी पूरी की गई
- अमृत राज्य योजना के तहत समूचे मिशन अवधि के लिए 1507 करोड़ रुपए

राष्ट्र के वैभव में व्यक्ति का वैभव

(12 जून, 1959 को संघ शिक्षा वर्ग, दिल्ली में दिए गए बौद्धिक का प्रथम भाग)

दीनदयाल उपाध्याय

जिन संस्कारों के परिणामस्वरूप सामूहिक भावनाओं की सृष्टि राष्ट्र में होती है, उन संस्कारों को समुच्चय भाववाचक जो नाम मिला है- वह संस्कृति है। उस राष्ट्र की जो अपनी विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर ही उस राष्ट्र में सामूहिक भावना की सृष्टि होती है। इसी संस्कृति की विभिन्नता के कारण प्रत्येक राष्ट्र के जीवन के व्यवहारों, आदर्शों, आचार, धर्म और ऐसी ही अन्य अनेक बातों का अंतर दिखाई देता है। जहां तक अपने देश का संबंध है, हमारी जो कुछ मूलभूत विशेषता है, उसके आधार पर हम व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के संबंध किसी स्वार्थ के सहारे स्थापित नहीं करते। हम किसी व्यक्ति के साथ भलाई इसलिए नहीं करते कि कल वह भी हमारे साथ भलाई करेगा। हम दस लोग इसलिए एकत्र नहीं खड़े कि दसों की स्वार्थ-सिद्धि होगी। यह तो व्यापारिक कल्पना है। यह कल्पना तो चोर, लुटेरों, डाकुओं में भी आ सकती है। वे भी अपना आचार-धर्म निर्माण कर सकते हैं। अपने में अनुशासन भी ला सकते हैं।

हिंदू ने आपसी संबंधों को इस नाते से नहीं देखा। हमारे यहां सामूहिक जीवन की कल्पना व्यक्ति-व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं की। यह तो कोई भी समझ सकता है कि राष्ट्र के वैभव में व्यक्ति का वैभव छिपा है, किंतु हमने अपनी संस्कृति के आधार पर निस्वार्थ वृत्ति को ही अपने संबंधों का कारण बनाया है। मैं समाज के लिए काम करूंगा। उसमें जो कुछ प्राप्ति होगी, वही मेरा प्राप्तव्य होगा।' बस इसी में सुख का अनुभव होगा। यह हमारा आदर्श है। हमारी राष्ट्रीयता की कल्पना कोई Selfishness extended विस्तारित स्वार्थपरता नहीं है। इसलिए हमने प्रतिज्ञा में भी यह शब्द प्रयोग किया कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म तथा समाज का संरक्षण करना चाहते हैं। लेशमात्र भी स्वार्थ नहीं रखते। हम स्वार्थ के लिए भी तो समाज का काम कर सकते हैं और यह सभी प्रकार के कामों में हो सकता है।

व्यक्ति विचार कर सकता है कि मैं कुछ काम करूंगा, इससे सामर्थ्य बढ़ेगी, वैभव आएगा तो मुझे भी उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन हमने निश्चय किया है कि हम सब कार्य निस्वार्थ बुद्धि से करेंगे। यदि इस प्रकार निस्स्वार्थ बुद्धि से हम कार्य करेंगे तो इसके जो संस्कार हम पर पड़ेंगे, तो वे अपनी संस्कृति के अनुकूल ही होंगे। मानो कोई किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर संघ की शाखा में आता है तो उस पर योग्य संस्कार नहीं पड़ेंगे। बाह्य रूप से बेशक कुछ परिवर्तन दिखाई दे, लेकिन आंतरिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे व्यक्तिगत रूप में स्वार्थ के आधार पर संबंध स्थापित हो सकते हैं, उसी प्रकार स्वार्थ के आधार पर हम शायद राष्ट्रीयता का जागरण कर लें, लेकिन हम उससे हिंदू राष्ट्र का जीवन खड़ा हुआ, नहीं कहेंगे। कुछ करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने कुछ वैभव भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें शायद आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे यहां सारा व्यवहार, विचार निस्स्वार्थ भाव के आधार पर ही किया गया है।

हम स्वयंसेवक अपनी संघशाखा में आते हैं। प्रश्न उत्पन्न होगा कि एक स्वयंसेवक दूसरे से कैसा व्यवहार करे? इसपर थोड़ा सा विचार करें तो जो गुण इस दृष्टि से चाहिए, वे हिंदू संस्कृति के संस्कार-स्वरूप ही होंगे। स्वयंसेवकों के बीच में पहली बात देखते हैं तो प्रेम का संबंध रहता है, वह भी निस्स्वार्थ भाव से रहता है। निरहेतुक होता है, केवल हिंदू होने के नाते। मान लो, कहीं कोई स्वयंसेवक दूर सफर पर चला आता है। गाड़ी में उसे एक और स्वयंसेवक उसी स्थान का मिल जाता है। उससे मिलकर जो भाव पैदा होता है, जो आकर्षण पैदा होता है, जरा सोचिए, क्या उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा रहता है। यह बात अलग है कि उस स्वयंसेवक के कारण उसे कहीं ठहरने की सुविधा प्राप्त हो जाती है, लेकिन किसी स्वयंसेवक के मन में यह बात नहीं आती। यदि किसी के मन में ऐसा आ गया तो समझो कि उसके मन का स्वयंसेवक गया। किसी को हम शाखा में लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्या इसलिए लाते हैं कि कल को अपने को भी नौकर की जरूरत पड़ गई तो ठीक रहेगा। ऐसी बात नहीं है।

हमारे यहां सामूहिक जीवन की कल्पना व्यक्ति-व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं की। यह तो कोई भी समझ सकता है कि राष्ट्र के वैभव में व्यक्ति का वैभव छिपा है, किंतु हमने अपनी संस्कृति के आधार पर निस्वार्थ वृत्ति को ही अपने संबंधों का कारण बनाया है। मैं समाज के लिए काम करूंगा। उसमें जो कुछ प्राप्ति होगी, वही मेरा प्राप्तव्य होगा।' बस इसी में सुख का अनुभव होगा। यह हमारा आदर्श है।

वह तो केवल हिंदू के नाते से आता है। उसके साथ जो स्वाभाविक प्रेम है, आत्मीयता है, उसे देखकर ही आता है। जब वह इस दृष्टि से देखता है तो वे सब बातें पैदा होने लगती हैं, जो अपनी संस्कृति की देन हैं।

प्रेम के साथ ही फिर सहिष्णुता पैदा होगी। कई लोग सहिष्णुता का अर्थ समझते हैं। कि कोई व्यक्ति जो कुछ कहता, करता रहता है, उसे सहन कर लेना सहिष्णुता है। जिसे अंग्रेजी में टॉलरेंस कहते हैं। यह टॉलरेंस मात्र है। सहिष्णुता इससे दो क़दम आगे है। टॉलरेंस में एक पराएपन का, दूरी का भाव रहता है। जैसे गाड़ी में कोई बच्चा शरारत करता है, किसी की चीजें इधर-उधर करता है या अन्य प्रकार की गड़बड़ी करता है तो हम सोचते हैं कि चलो, ठीक है। बच्चा है, कर लेने दो। कमजोरी के कारण भी यह भाव उत्पन्न होता है। अब क्या करें, लड़ें क्या? ऐसा भाव रहता है।

सहिष्णुता के पीछे ऐसी कोई कमज़ोरी का भाव नहीं है और न ही कोई पराएपन का भाव है। उल्टे, यहां तो अपनेपन के कारण दूसरे की बात के प्रति ध्यान देना; उसमें भी कुछ ठीक हो सकता है, उस पर विचार करें। एक और इच्छा भी छिपी कि जो उसमें कुछ बुरा है, उसे कैसे दूर किया जाए, इस प्रकार उसकी कमियों के प्रति प्रेमपूर्ण उपचार करने की दृष्टि रखना, इतना ही है। टॉलरेंस से तो कुछ लोग कह सकते हैं कि अपने सत्य पर विश्वास ही नहीं रहता। वास्तव में कई उसे बहुत दूर तक ले भी गए। मेरा भी कहना ठीक हो सकता है, दूसरों का कहना भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सोचता है कि अंतिम सत्य कितना कठिन है। जैसे किसी ने अंग्रेजों के यहां किसी से पूछा कि वह व्यक्ति अंदर है क्या? तो उत्तर देने वाला कहेगा, "मुझे लगता है कि वह वहां नहीं है और यदि वह आदमी वहां नहीं हुआ, तो वह उत्तर देने वाला कहेगा, मुझे डर है कि वह वहां नहीं है, अब वह विश्वास के साथ कहता है कि वह है या नहीं है। यह जो मुझे है और डर वाली भाषा है, क्या यह प्रकट नहीं करती कि अपने प्रति अविश्वास है। हो सकता है, मेरा कहना गलत हो, लेकिन हमारे यहां यह श्रद्धा कि उसके अंदर यह सच्चाई हो सकती है। परंतु उसके साथ ही प्रेम से उसके अंदर की कमी को सुधारने का भाव भी छिपा हुआ है।

उदाहरण ही लेना हो तो घर में एक छोटे से बच्चे का लें। मान लो वह अपनी तोतली भाषा में मांगता है, समझ में आता नहीं तो क्या करते? गाली देते? नहीं, उसकी भाषा के पीछे उसका मतलब क्या है, यह टटोलते। मुझे एक बच्चे की बात याद आई। वह कहता था, अटू-अटू। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उसे लड्डू दिया, उसने नहीं लिया। फिर सोचा शायद यह सत्तू मांगता हो। वह भी उसने नहीं लिया। वास्तव में वह लट्टू मांग रहा था। लटू मिलने पर वह खुश हो गया। पश्चिम की टॉलरेंस तो कहेगी कि इसे चिल्लाने दो, इसको बोलने का अधिकार है, इसे बोलने दो। वाल्टेयर ने इस दृष्टि से कहा है कि यद्यपि तुम्हारे कहने पर मुझे विश्वास नहीं, पर तुम्हारे बोलने के अधिकार के लिए मैं आख़िरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन हम इससे भी आगे गए हैं। दूसरों में भी सच्चाई ढूंढ़कर उस सच्चाई को अपनी सच्चाई के साथ समन्वय का प्रयास हम करते हैं। यह सहिष्णुता हमारी संस्कृति का प्रमुख गुण है।

व्यक्ति विचार कर सकता है कि मैं कुछ काम करूंगा, इससे सामर्थ्य बढ़ेगी, वैभव आएगा तो मुझे भी उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन हमने निश्चय किया है कि हम सब कार्य निस्वार्थ बुद्धि से करेंगे। यदि इस प्रकार निस्वार्थ बुद्धि से हम कार्य करेंगे तो इसके जो संस्कार हम पर पड़ेंगे, तो वे अपनी संस्कृति के अनुकूल ही होंगे।

कोई नया स्वयंसेवक जब शाखा में आता है तो वह यहां का विचार सुनने के पश्चात् कई बार हमारे विचार को संकुचित कहता है, कभी सांप्रदायिक बताता है, परंतु हम उसकी सब बातों को बड़े आराम से सुनते हैं। इसलिए नहीं कि हममें टॉलरेंस का भाव है। न ही हम उसे यह कहते कि यदि तुम ऐसा सोचते हो तो कल से मत आना। उसके ख़िलाफ़ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी नहीं सोचते। तो क्या करते हैं, उसकी बात को सुन लेते हैं और बाद में समझाने का प्रयत्न करते हैं। उसे एक पक्का हिंदू राष्ट्रवादी और निष्ठावान स्वयंसेवक बनाकर छोड़ते हैं। हमारी संस्कृति का यह जो प्रमुख गुण है, शाखा में काम करते हुए जब इस प्रकार का प्रेम जाग्रत् होता है तो सेवावृत्ति भी जागती है।

जब किसी स्वयंसेवक के जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, वह बीमार हो जाता है अथवा अन्य कोई कष्ट आ पड़ता है, तब हम उसकी सहायता, सेवा एवं दवा-दारू करते हैं। इसलिए नहीं कि कल हमें भी कोई कष्ट या रोग घेर सकता है। इतना नहीं तो जो स्वयंसेवक बीमार या कष्ट में होता है, वह इसकी अपेक्षा भी नहीं करता। वह सोचता है कि उस वक्त में इन स्वयंसेवकों को मेरी देखभाल छोड़कर कुछ नए स्वयंसेवक बनाने चाहिए, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तब ज्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार दोनों ओर कार्य के अनुरूप व्यवहार होने लगता है।

एक बार एक स्वयंसेवक को मुझे मालूम है कि वह बीमार पड़ गया। उसकी ख़बरगिरी के लिए स्वयंसेवक गए तो सही, पर ज्यादा नहीं। एक बार मैं घूमते हुए उधर जा निकला तो वह भी मिला। बड़ा नाराज सा था। कहने लगा कि मैंने इतना काम किया, संघ को इतना समय देता रहा, अपने घर-बार को छोड़ा। यह भाव उसके मन में आ गया। इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम मानव की कमजोरी कहकर टाल सकते हैं। पर हिंदू संस्कृति का यह आधार नहीं। हमने आपसी संबंधों की दृष्टि से ऐसा अपेक्षा का भाव कभी निर्माण नहीं किया। ■

क्रमशः

'महामना' पंडित मदन मोहन मालवीय

(25 दिसम्बर, 1861– 12 नवम्बर, 1946)

'महामना' पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान् स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद और बड़े समाज सुधारक थे। 'महामना' मालवीय देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मन्दिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के ख़िलाफ़ देशभर में आंदोलन चलाया। पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

इलाहाबाद में 25 दिसम्बर, 1861 में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान् कार्यों के चलते 'महामना' कहलाये। इनके पिता का नाम श्री ब्रजनाथ और माता का नाम श्रीमती भूनादेवी था। चूंकि ये लोग मालवा के मूल निवासी थे, इसीलिए मालवीय कहलाए। महामना मालवीय जी ने सन् 1884 में उच्च शिक्षा समाप्त की। शिक्षा समाप्त करते ही उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया, पर जब कभी अवसर मिलता वे किसी पत्र इत्यादि के लिये लेखादि लिखते। 1885 ई. में वे एक स्कूल में अध्यापक हो गये, परन्तु शीघ्र ही वक़ालत का पेशा अपना कर 1893 ई. में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वक़ील के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और 1885 तथा 1907 ई. के बीच तीन पत्रों- हिन्दुस्तान, इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय का सम्पादन किया।

मदन मोहन मालवीय की प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद के श्री धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला में हुई। इसके बाद मालवीयजी ने 1879 में इलाहाबाद ज़िला स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की और म्योर सेंट्रल कॉलेज से एफ.ए. की। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मदन मोहन को कभी-कभी फ़ीस के भी लाले पड़ जाते थे। इस आर्थिक विपन्नता के कारण बी.ए. करने के बाद ही मालवीयजी ने एक सरकारी विद्यालय में 40 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापकी शुरू कर दी।

मालवीय जी एक सफल पत्रकार थे और हिन्दी पत्रकारिता से ही उन्होंने जीवन के कर्मक्षेत्र में पदार्पण किया। वास्तव में मालवीय जी ने पत्रों को हिन्दी-प्रचार का प्रमुख साधन बना लिया। हिन्दी आन्दोलन के सर्वप्रथम नेता होने के कारण मालवीय जी पर हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि का दायित्व भी आ गया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सन् 1910 ई. में उनकी सहायता से इलाहाबाद में 'अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन' की स्थापना हुई। उसी वर्ष अक्टूबर में सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ, जिसके सभापति मालवीय जी थे। महामना मालवीय जी अपने युग के प्रधान नेताओं में थे। जिन्होंने हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान को सर्वोच्च स्थान पर प्रस्थापित कराया।

मालवीय ने असहयोग आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय, जवाहर लाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर साइमन कमीशन का ज़बर्दस्त विरोध किया और इसके ख़िलाफ़ देशभर में जनजागरण अभियान भी चलाया। महामना तुष्टीकरण की नीतियों के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने 1916 के लखनऊ पैक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया। वह देश का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया।

पं. मदन मोहन मालवीय जी कई संस्थाओं के संस्थापक तथा कई पत्रिकाओं के सम्पादक रहे। इस रूप में वे हिन्दू आदर्शों, सनातन धर्म तथा संस्कारों के पालन द्वारा राष्ट्र-निर्माण की पहल की थी। इस दिशा में 'प्रयाग हिन्दू सभा' की स्थापना कर समसामयिक समस्याओं के संबंध में विचार व्यक्त करते रहे। सन् 1884 ई. में वे हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सन् 1885 ई. में 'इण्डियन यूनियन' का सम्पादन, सन् 1887 ई. में 'भारत-धर्म महामण्डल' की स्थापना कर सनातन धर्म के प्रचार का कार्य किया। सन् 1889 ई. में 'हिन्दुस्तान' का सम्पादन, 1891 ई. में 'इण्डियन ओपीनियन' का सम्पादन कर उन्होंने पत्रकारिता को नई दिशा दी। इसके साथ ही सन् 1891 ई. में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते हुए अनेक महत्त्वपूर्ण व विशिष्ट मामलों में अपना लोहा मनवाया था। सन् 1913 ई. में वकालत छोड़ दी और राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया, ताकि राष्ट्र को स्वाधीन देख सकें। मालवीय जी ने सन् 1916 ई. में 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना की। वास्तव में यह ऐतिहासिक कार्य शिक्षा और साहित्य सेवा का अमिट शिलालेख है। मालवीयजी आजीवन देश सेवा में लगे रहे और 12 नवम्बर, 1946 ई. को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। ■

अटलजी: सौहार्द के महान् दूत और नेता

डॉ. मुरली मनोहर जोशी

प्रधानमंत्री अटल, विदेश मंत्री अटल, वक्ता अटल, राजनेता अटल और इन सारे विशेषणों के साथ-साथ मैं उस सामान्य मनुष्य अटल, सौहार्द के दूत अटल और ऐसे अटल को भी जानता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जगत् में इंसानियत और मेल-मिलाप पर आधारित राजनीतिक आचार की शुरुआत की, जो एक नई मिसाल थी। वे स्थानीय और वैश्विक स्तर पर लोगों से जुड़ने में तथा मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास रखते थे।

उनका मानवीय हृदय क्षणभर में उन्हें लोगों से जोड़ देता था और उन्होंने इस गुण को सांस्कृतिक, सभ्यता संबंधी, आध्यात्मिक, संरचनात्मक जुड़ाव में परिवर्तित किया। अटलजी ने लोगों, गांवों, शहरों, देशों और विविध राजनीतिक विचारधाराओं तक को भी आपस में जोड़कर भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों का एक ऐसा गठबंधन बनाया, जो राज-काज में एक नई शुरुआत थी और जिसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।

वर्ष 2003 में नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से 'सभ्यताओं के बीच बातचीत' विषय पर आयोजित सम्मेलन में व्यक्त किए गए उनके विचार वैश्विक समस्याओं को लेकर उनकी चिंता का संकेत दे रहे थे। साथ ही, इस संसार में समन्वय और शांति की ओर निरंतर अग्रसर रहने वाली सभ्यता के लिए सभ्यताओं के बीच बातचीत की एक नई कला व विज्ञान को अनिवार्य साधन के रूप में विकसित करने की गहरी इच्छा की ओर भी इशारा कर रहे थे। वाजपेयी देशों, महादेशों, सभ्यताओं और इस संसार के लोगों के बीच सामंजस्य एवं मेल-जोल का एक जीवंत माहौल बनाने में विश्वास रखते थे। वे बातचीत के जरिए अंतरराष्ट्रीय मामलों को चलाने का एक उदाहरण दिखाना चाहते थे, जो विविधता की पहचान पर आधारित हो और मेल-मिलाप के जरिए विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच सौहार्द कायम करता हो। मैं वाजपेयी को सौहार्द बनाने वाला और मेल-मिलाप बढ़ानेवाला आधुनिक भारत का एक सबसे महान् नेता मानता हूं।

सबको एक सूत्र में पिरोनेवाले महान् नेता के रूप में कनेक्टिविटी वाजपेयी का मूलमंत्र था। लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने बुनियादी संरचना का उपयोग एक मंच के रूप में किया, जब उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत देश के चारों कोनों को आपस में जोड़ा। इसे दुनिया की सबसे लंबा जन-राजमार्ग परियोजनाओं में से एक कहा जाता है, जिसकी लंबाई 5846 कि.मी. है, जिसका लक्ष्य भारत के प्रमुख कृषि संबंधी, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ना है। एक तरफ स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी तो दूसरी तरफ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' को भी उतना ही महत्त्व दिया, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत मिली। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय भी बनाया, ताकि इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सके।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपर्क राजमार्गों के माध्यम से केवल ठोस बुनियादी संरचना तक ही सीमित न रहे, उन्होंने राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के माध्यम से 'कनेक्टेड इंडिया' की नींव भी रखी, जो टेक्नोलॉजी हाइवे थी। इससे दुनिया का सबसे बड़ा और किफायती टेलीकॉम बाजार बनाने में मदद मिली, जिससे आई.टी. क्रांति को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। आज यदि भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ग्राहकों वाला देश है, तो यह अटलजी की उन नीतियों के कारण है, जिन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के लिए रोडमैप बनाया।

भारत के प्रवासियों की संख्या 1.6 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे अधिक है; 'प्रवासी भारतीय दिवस' अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग की ही उपज थी। वे दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों को जोड़ना और भारत में उनकी दिलचस्पी को फिर से जगाना चाहते

थे। यह दुनिया भर में बिखरे भारतीयों को जोड़ने वाला सबसे अनोखा कार्यक्रम था। इसका परिणाम भारतीयों के वापस लौटने या भारत में निवेश करने के रूप में भी सामने आया।

'लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए। वाजपेयी ने क्षेत्रीय कूटनीति के महत्त्व को भी समझा। उनकी यह नीति दक्षिण-पूर्व के एशियाई देशों के साथ विस्तृत आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने में मास्टर स्ट्रोक थी। इसने भारत की छवि एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बढ़ाई तथा चीन के रणनीतिक प्रभाव के मुकाबले में ला खड़ा किया। उनकी विदेश नीति एक तरफ महाशक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने पर आधारित थी, तो दूसरी तरफ लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से पड़ोसियों को समान महत्त्व देती थी। इन सबका उद्देश्य सबको साथ लेकर चलना और भारत के हितों को सर्वोपरि रखना भी था।

बात जब एक सशक्त भारत को सुनिश्चित करने की आई, तब उन्होंने न केवल पोखरण में परमाणु विस्फोट करने का निर्णायक कदम उठाया, बल्कि वे अपने फैसले पर अडिग रहे और भारत का कद एक परमाणु शक्ति का बना दिया, जिसे सात दशकों तक हासिल नहीं किया जा सका था। पोखरण के धमाके के बाद भारत को कठोर वैश्विक प्रतिबंध से डराया गया। पर्याप्त परिपक्वता और कौशल के साथ उन्होंने देश को इस स्थिति से निकाला, अमेरिका के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट तथा रूस के साथ मास्को समझौते पर दस्तखत किए। वाजपेयी ने चीन से भी बातचीत की और सीमा विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए एस.आर. जैसी प्रणाली को स्थापित किया। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ इराक में भारतीय सेना को भेजने के अमेरिकी आग्रह को ठुकरा दिया।

'अंत्योदय' को लागू करने के लिए उन्होंने किसानों को उच्च प्राथमिकता दी। किसानों का कल्याण उनके दिल के बेहद करीब था और उन्होंने सुनिश्चित किया कि क्रेडिट कार्ड केवल अमीर लोगों की हैसियत की पहचान ही न रहे, बल्कि एक गरीब किसान की बुनियादी जरूरत बने, इसलिए किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। लोक कल्याण और शासन में वाजपेयी ने एकदम नई सोच का परिचय दिया।

अटलजी ने विकास के लिए शिक्षा और तकनीक के महत्त्व को समझा तथा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए 'सर्व शिक्षा अभियान' की शुरुआत की और लोगों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा। यह संसार में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में सबसे बड़ा शैक्षिक कार्यक्रम था।

अटल बिहारी वाजपेयी अपने अभियान में जुटे रहने वाले व्यक्ति थे, जो अपनी दृष्टि, शब्दों और कर्मों से आम सहमति बनाने वाले महान् नेता बने। वे गठबंधन वाली सरकार, सामंजस्य की राजनीति तथा समावेशी विकास के जनक बने। अटलजी ने दुनिया को 'अटल की मिसाल' के एक नए राजनीतिक व्यवहार को दिखाया है। अटलजी अमर रहेंगे और उनके योगदानों ने नए भारत के भविष्य को स्वरूप दिया है।

उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही पहली बार विभिन्न स्थानों पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान' खोले गए और ज्ञान संपन्न समाज की रचना के बीज बोए गए। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के 'जय जवान जय किसान' के नारे को आगे बढ़ाते हुए 'जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान' का नारा दिया।

अटलजी के युग को उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण भारत के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। एवं इसके फलस्वरूप भारत की जी.डी.पी. आठ प्रतिशत की स्थिर दर से बढ़ती चली गई, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। मुद्रास्फीति नियंत्रित थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा था, जबकि यह वैश्विक अनिश्चितताओं का दौर था तथा निश्चित रूप से यह एशियाई संकट के दौरान कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी।

अटल युग सबको शामिल करने वाले दृष्टिकोण के लिए जाना गया, जहां विचारों में अंतर हो सकता था, लेकिन आखिर में आम सहमति होती थी। उन्होंने देश को उस जड़ता की स्थिति से निर्णायक ढंग से बाहर निकाला, जिसमें वह दशकों से जकड़ा हुआ था। उन्होंने न केवल विभिन्न विचारधाराओं को आपस में जोड़ा, बल्कि विविधता भरे गठबंधन में तालमेल बिठाते हुए व्यापक सुधारों पर भी अमल किया। वे मौलिक भारतीय दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'अनेकता में एकता' और 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' (एक ही सत्य को विद्वान् लोग बहुत प्रकार से बताते हैं) में विश्वास करते थे। उनका राजनीतिक व्यवहार इन्हीं सिद्धांतों को दर्शाता था।

अटल बिहारी वाजपेयी अपने अभियान में जुटे रहने वाले व्यक्ति थे, जो अपनी दृष्टि, शब्दों और कर्मों से आम सहमति बनाने वाले महान् नेता बने। वे गठबंधन वाली सरकार, सामंजस्य की राजनीति तथा समावेशी विकास के जनक बने। अटलजी ने दुनिया को 'अटल की मिसाल' के एक नए राजनीतिक व्यवहार को दिखाया है। अटलजी अमर रहेंगे और उनके योगदानों ने नए भारत के भविष्य को स्वरूप दिया है। अटलजी के साथ मेरे संबंध को किसी एक लेख में, केवल आमने-सामने के अनुभवों से नहीं बताया जा सकता, बल्कि इतनी बहुमुखी हस्ती, एक महान् राजनेता को, उनकी सोच, उनके विचारों, राजनीति की उनकी शैली और सच कहूं तो उन सारी बातों से समझा जा सकता है, जिन्होंने एक गौरवशाली युग की दिशा में हमें आगे बढ़ाया है। ■

(साभार : साहित्य अमृत)

(लेखक भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

ग्रामीण भारत: यूपीए और एनडीए सरकारों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन

अरुण जेटली

हाल में कई किसान संगठनों ने दिल्ली में एक विरोध मार्च आयोजित किया। इस मार्च में मुख्य रूप से विपक्षी दलों और वामपंथी मोर्चों से संबंधित संगठनों ने हिस्सा लिया। वे ग्रामीण इलाकों में संकटजनक हालात को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने सरकार पर ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र की अनदेखा करने का भी आरोप लगाया।

वस्तुस्थिति क्या है

नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 मई, 2014 को पदभार संभाला था। इसके बाद कृषि क्षेत्र में दबाव पैदा नहीं हुआ। यह कांग्रेस द्वारा कृषि क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की अपर्याप्तता थी, जिसने ग्रामीण इलाकों में कृषि संकट और अल्प गुणवत्ता दोनों को ही जन्म दिया था। एनडीए सरकार ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, निवेश बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुपक्षीय रणनीति बनाई, जिसमें राज्य पर किसानों की निर्भरता कम करने और कृषि को लाभकारी बनाने का प्रयास किया गया।

गांव के लिए मूलभूत सुविधाएं

ग्रामीण इलाकों के विकास में सड़कों की अहम् भूमिका रही है, यह सड़कें न केवल किसानों के उत्पाद को बाजार लाने ले जाने में सुगमता प्रदान करती हैं, वहीं ये सड़कें ग्रामीण आबादी को शहरों से भी जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कार्यभार संभाला था, तो स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद 3.8 लाख किमी सड़कों का ही निर्माण किया गया था। वहीं, नवंबर, 2018 तक, यह आंकड़ा 5.7 लाख किलोमीटर हो गया है। पिछले साढ़े चार सालों में ग्रामीण इलाकों में 1.9 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण सड़कों में निवेश तीन गुना बढ़ गया है। बहुत जल्द हम प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।

भारत में 16.53 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं। आजादी के 67 वर्ष के बाद भी साल 2013-14 तक देश में केवल 70% ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण किया गया था। वहीं, हमारी सरकार ने नवंबर, 2018 तक 16.53 करोड़ परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, जिसके चलते यह आंकड़ा अब 95 प्रतिशत हो गया है और अगले कुछ हफ्तों में ग्रामीण विद्युतीकरण का यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

जहां तक ग्रामीण आवास का संबंध है, यूपीए सरकार के अंतिम वर्ष में ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए एक वर्ष में करीब 10 लाख घर बनाए गए थे। यह आंकड़ा आज साढ़े चार गुना बढ़ गया है और अब लगभग 45 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में आवास योजना को अभूतपूर्व सफलता मिली है। हमें उम्मीद है कि साल 2022 तक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास पक्का मकान होगा।

ग्रामीण इलाकों में जहां 2 अक्टूबर, 2014 तक केवल 38.7% परिवार ही स्वच्छता कवरेज के दायरे में आते थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद यह आंकड़ा नवंबर, 2018 को 96.72% हो गया है।

ऐसे ही 21 नवंबर, 2018 तक 33.3 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं, जिसके माध्यम से आज लगभग सभी नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

साल 2017 में गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्ज्वला

योजना शुरू की गई थी और लगभग डेढ़ वर्षों के दौरान 5.8 करोड़ परिवार को गैस कनेक्शन दिए जा चुके है। यह आंकड़ा 31.03.2019 तक 8 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

आज लगभग तेरह करोड़ परिवार मुद्रा लोन का लाभ उठा रहे हैं और लोन प्राप्त करने वालों में 54% महिलाएं भी शामिल हैं।

भारत में गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का शुभांरभ किया, इसमें भी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि आजादी के 67 सालों बाद भी देश के इस कमजोर तबके के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थी। इस योजना का लाभ भारत के सबसे गरीब 10 करोड़ (भारत की आबादी का 40%) परिवारों को होगा, जिसके तहत यह परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कर निर्दिष्ट बीमारियों का सही इलाज अस्पताल के माध्यम से करवा सकेंगे। इस योजना के शुभांरभ के बाद पिछले दो महीनों में लगभग 3.8 लाख लोगों इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

किसानों की आय

सरकार ने किसानों की उत्पादकता में वृद्धि और उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन पर अपने खर्च में वृद्धि की है। ऐसे ही कृषि अनुसंधान और शिक्षा में निवेश को बढ़ाया गया है। वहीं, सिंचाई में भी निवेश पर काफी वृद्धि हुई है। ग्रामीण रोजगार योजना 'मनरेगा' के तहत सबसे कमजोर तबके के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो यूपीए सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का लगभग दोगुना है। गरीब परिवारों के लिए खाद्य सब्सिडी के तहत 1.6 लाख करोड़ की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कुछ चुनिंदा उत्पादों पर लागत का 50% अधिक एमएसपी दिया जा रहा है। ब्याज के संदर्भ में भी दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दोगुना कर दिया गया है। पिछले साल (2017-18) 3,96,831 करोड़ रुपये ग्रामीण इलाकों में खर्च किए गए थे। वहीं इस साल यह खर्च करीब 4,38,741 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। जबकि यूपीए सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में 2,41,602 करोड़ रुपये की राशि ही ग्रामीण इलाकों के लिए आवंटित की थी।

कृषि संकट को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केवल नारे देने से काम नहीं चलेगा। जैसाकि 1971 से कांग्रेस करती आयी है, कांग्रेस द्वारा बनाई गई नीतियों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह संसाधन कम और नारे ज्यादा थे। एनडीए ने ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का विस्तार किया है। इन संसाधनों ने हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, स्थानीय निवासियों के जीवन में लगातार सुधार हो रहा है और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। हमारा उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। पिछले साढ़े चार सालों में किए गए सुधार कार्य इस दिशा में केवल शुरुआत भर है। यदि हम इसी गति से अगले दो दशकों तक ग्रामीण इलाकों में निवेश को जारी रखने में कामयाब हो जाते है, तो हम ग्रामीण इलाकों में बेहतर जीवन स्तर और आवश्यक बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के करीब होंगे, जो लगभग शहरी इलाकों जैसा होगा। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त मंत्री है)

कृषि संकट को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केवल नारे देने से काम नहीं चलेगा। जैसाकि 1971 से कांग्रेस करती आयी है, कांग्रेस द्वारा बनाई गई नीतियों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह संसाधन कम और नारे ज्यादा थे। एनडीए ने ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का विस्तार किया है। इन संसाधनों ने हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, स्थानीय निवासियों के जीवन में लगातार सुधार हो रहा है और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु नौ सूत्री एजेंडा का सुझाव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु 29 नवंबर से 01 दिसंबर तक ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) की यात्रा की। शिखर सम्मेलन में भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति का पता लगाने के लिए जी-20 में नौ सूत्री एजेंडा का सुझाव दिया। शिखर सम्मेलन के इतर भारत-जापान-अमेरिका तथा भारत-रूस-चीन के मध्य त्रिपक्षीय बैठकें हुईं। इसके अलावा श्री मोदी ने न केवल चीन के राष्ट्रपति श्री शी चिनफिंग के साथ मुलाकात की, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमैनुअल मैक्रां से भी बातचीत की। साथ ही प्रधानमंत्री ने वहां पर आयोजित योग कार्यक्रम में भी भाग लिया।

ब्यूनस आयर्स में हालिया संपन्न हुए 13वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 30 नवंबर को भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति का पता लगाने के लिए जी-20 में नौ सूत्री एजेंडा का सुझाव दिया। इस एजेंडा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खतरे से व्यापक और कुशलतापूर्वक निपटने के लिए जी-20 देशों में एक मजबूत और सक्रिय सहयोग, अपराध से प्राप्त आय की प्रभावी जब्ती, अपराधियों की जल्द से जल्द वापसी और अपराधिक आय को प्रभावी रूप से स्वदेश लौटाने जैसी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ाना और सुव्यवस्थित करना, सभी भगोड़े आर्थिक अपराधियों का दूसरे देशों में प्रवेश और उनके सुरक्षित आश्रय को रोकने के लिए जी-20 देशों द्वारा एक कार्य प्रणाली बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करना प्रमुख हैं।

इसके अलावा एजेंडा में कहा गया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतों (यूएनसीएसी), अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनओटीसी) के बारे में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को पूरी तरह और प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने पर जोर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवंबर को जी 20 शिखर सम्मेलन के इतर ब्रिक्स नेताओ की बैठक के दौरान कहा कि हम ब्रिक्स में विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ब्रिक्स ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। हालांकि, अभी भी विश्व GDP (23%) और ट्रेड (16%) में हमारे हिस्से के बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। वह जनसंख्या के अनुरूप नहीं हैं।

श्री मोदी ने कहा कि वैश्वीकरण ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि, वैश्वीकरण के फायदों के समान वितरण को लेकर

हमारे सामने चुनौतियां हैं। मल्टीलेटरलिज्म और नियम-आधारित विश्व-व्यवस्था के सामने निरंतर कठिनाइयां आ रही हैं और प्रोटेक्शनिज़्म बढ़ रहा है। मुद्रा अवमूल्यन और तेल कीमतों में तेज बढ़ोत्तरी पिछले कुछ वर्षों में अर्जित लाभ को चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक स्थिरता और विकास में योगदान देते रहे हैं। हमने विश्व की आर्थिक और राजनैतिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत–जापान–अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 30 नवम्बर को अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के साथ अत्यंत मैत्रीपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रपति श्री ट्रम्प और प्रधानमंत्री श्री आबे ने श्री मोदी द्वारा किए जा रहे सुधार और विकास कार्यों के लिए उनकी सराहना की तथा तीनों नेताओं ने भारत-प्रशांत पर विचारों का आदान-प्रदान किया। वे सभी सहमत थे कि क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए एक मुक्त, खुली, अंतर्वेशी और नियम आधारित व्यवस्था अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए कि किस प्रकार हमें भारत-प्रशांत की अवधारणा को आगे ले जाना चाहिए और किस प्रकार तीनों देश इस अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर सकते हैं। श्री मोदी ने विशेष रूप से यह महसूस किया कि तीनों देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी हितधारकों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भारत-प्रशांत कार्यनीति और इन देशों के लिए उसके लाभों के बारे में बताया जा सके।

नेतागण आसियान की केंद्रीय भूमिका पर भी सहमत हुए तथा सामुद्रिक और संयोजन के मुद्दों पर कार्य करने और इस संबंध मे प्रयासों को अधिक सक्रिय बनाने पर भी सहमत हुए। सभी तीनों नेताओं ने यह महसूस किया कि ऐसी बैठकें उपयोगी हैं और आने वाली जी20 बैठकों के दौरान भी इन्हें जारी रखा जाना चाहिए। जापान-अमेरिका-भारत त्रिपक्षीय बैठक का परिणाम बहुत ही प्रोत्साहनजनक रहा है और अन्य दोनों नेता भी इसके परिणाम से अत्यंत प्रसन्न थे।

रूस–भारत–चीन के मध्य त्रिपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने 30 नवम्बर को ब्यूनस आयर्स में एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया। तीनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय मंचों में आपसी सहयोग को बढ़ाने और तीनों देशों के बीच बेहतर बातचीत को बढ़ावा देने के बारे में बातचीत की। उन्होंने ऐसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करने और मजबूती प्रदान करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की, जिनसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अच्छी तरह से स्थापित संस्थानों के साथ-साथ नये वैश्विक वित्तीय संस्थानों सहित पूरा विश्व लाभान्वित हुआ है। उन्होंने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और वैश्विक विकास तथा समृद्धि के लिए खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों को रेखांकित किया।

तीनों नेताओं ने ब्रिक्स, एससीओ और ईएएस तंत्रों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता तथा सहयोग को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर नियमित विचार-विमर्श करने के बारे में सहमति व्यक्त की, ताकि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सके और सभी मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के काम को प्रोत्साहित किया जा सके। तीनों नेताओं ने आरआईसी प्रारूप में सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए बहुपक्षीय अवसरों पर ऐसी त्रिपक्षीय बैठकों को आगे भी आयोजित करने पर सहमति दी।

भारत–चीन संबंधों में स्पष्ट सुधार हुआ है: नरेन्द्र मोदी और शी जिनपिंग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने 30 नवंबर को जी20 शिखर सम्मेलन से इतर आपसी भेंट के दौरान विविध क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि वुहान सम्मेलन के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में स्पष्ट सुधार हुआ है। इस साल अपनी चौथी मुलाकात में श्री मोदी और श्री शी ने दोनों मुल्कों के बीच आपसी विश्वास एवं मित्रता को और आगे बढ़ाने के संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने 30 नवंबर को जी20 शिखर सम्मेलन से इतर आपसी भेंट के दौरान विविध क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि वुहान सम्मेलन के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में स्पष्ट सुधार हुआ है। इस साल अपनी चौथी मुलाकात में श्री मोदी और श्री शी ने दोनों मुल्कों के बीच आपसी विश्वास एवं मित्रता को और आगे बढ़ाने के संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा की।

श्री मोदी और श्री शी अप्रैल में चीन के वुहान के अनौपचारिक सम्मेलन के बाद दो बार मुलाकात कर चुके हैं। दोनों जून में चीन के चिंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में मिले थे और फिर जुलाई में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई थी।

वुहान सम्मेलन को भारत चीन संबंधों में मील का पत्थर बताते हुए श्री मोदी ने श्री शी से कहा कि उन्हें अगले साल एक अनौपचारिक बैठक में उनकी मेजबानी करने की आशा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ''ऐसी पहलें (संबंधों में) गति बनाए रखने में मददगार साबित होती हैं।" उन्होंने कहा कि चिंगदाओ और जोहान्सबर्ग में दो समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री

ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों ने पिछले एक साल में काफी उन्नति की है। श्री मोदी ने कहा, ''इस मुलाकात के लिए वक्त निकालने को लेकर मैं आपको (राष्ट्रपति शी को) हार्दिक धन्यवाद देता हूं।"

श्री मोदी ने बाद में ट्वीट किया, ''अर्जेंटीना में जी-20 सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शानदार मुलाकात हुई। कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। हमारी लगातार बातचीत ने भारत और चीन के बीच संबंधों को काफी मजबूत किया है।"

भारत–फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को जी-20 शिखर बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमैनुअल मैक्रां से अलग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क बढ़ाकर द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी को और गहरा करने पर विचार विमर्श किया।

इसके अलावा दोनों नेताओं ने आतंकवाद के वित्तपोषण पर साझा मोर्चा, समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार के मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री मोदी ने ट्वीट किया, ''राष्ट्रपति मैक्रां के साथ शानदार बैठक हुई। हमारे बीच भारत-फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने और उसके विविधीकरण के जुड़े व्यापक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ।"

भारत– अर्जेंटीना में एक–दूसरे की संस्कृतियों के प्रति आदर भाव है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवम्बर को अर्जेंटीना में योग कार्यक्रम में कहा कि भारत और अर्जन्टीना के बीच 15 हजार किलोमीटर की दूरी है। हम दोनों देशों के बीच दो विशाल महासागर और महाद्वीप हैं। दोनों देशों के समय में 8 घंटे और तीस मिनट का अंतर है। यानी अभी आपकी शाम है, लेकिन भारत में लोग ब्रह्म मुहूर्त की साधना शुरू करने वाले हैं, फिर भी आपके योगाभ्यास ने दिखा दिया है कि भारत और अर्जेंटीना में एक-दूसरे की संस्कृतियों के प्रति आदर भाव के सामने हजारों किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक आंकड़ा मात्र है।

श्री मोदी ने कहा कि योग का अर्थ ही है जोड़ना। यह हमें वैलनेस से जोड़ता है। हैपीनेस से जोड़ता है और आज भारत और अर्जेंटीना के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को योग पाट रहा है और हमारे दोनों देशों को, हमारे लोगों को जोड़ रहा है। हमें एक आत्मीय संबंध से बांध रहा है। ■

पीएसएलवी-सी43 ने उपग्रह एचवाईएसआईएस और 30 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी43) ने 29 नवंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 31 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पीएसएलवी-सी43 ने प्रथम प्रक्षेपण स्थल से भारतीय समय के अनुसार 9:57:30 बजे उड़ान भरी। उड़ान भरने के 17 मिनट, 19 सैकेंड के बाद इसने भारत के हाईपर-स्पैक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह (हाईसिस) को 645 किलोमीटर के सन-सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्ष में स्थापित कर दिया। इसके बाद यान के चौथे चरण वाले इंजनों को दोबारा स्टार्ट करके 30 विदेशी उपग्रहों को उनके मनोनुकूल कक्ष में स्थापित किया गया। उड़ान भरने से लेकर एक घंटा, 49 मिनट के बाद अंतिम उपग्रह को इसके निर्धारित कक्ष में स्थापित किया गया।

इनके पृथक होने के बाद एचवाईएसआईएस के दोनों सौर शृंखलाएं स्वतः क्रियाशील हो गईं और बेंगलूरू स्थित इसरो के टेलीमेट्री ट्रेकिंग और कमांड नेटवर्क ने उपग्रह पर नियंत्रण कायम कर लिया। अगले कुछ दिनों में इस उपग्रह को अपने अंतिम संचालन विन्यास में लाया जाएगा। एचवाईएसआईएस के परियोजना निदेशक श्री सुरेश के. ने कहा कि प्रक्षेपण के बाद यह उपग्रह सामान्य रूप से काम कर रहा है। इसरो 5 दिसम्बर को अपने सबसे भारी उपग्रह जीएसएटी-11 का प्रक्षेपण करेगा। एचवाईएसआईएस एक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है। इसे इसरो के मिनी उपग्रह-2 के तर्ज पर बनाया गया है। इसका वजन लगभग 380 किलोग्राम है। उपग्रह का मिशन लाइफ पांच वर्ष है।

विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम के इन्फ्रारेड और शॉर्टवेव इन्फ्रारेड क्षेत्रों के निकट दोनों दृश्यमान क्षेत्रों मंथ पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना एचवाईएसआईएस का प्राथमिक लक्ष्य है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े का इस्तेमाल कृषि, वन, मृदा/भूगर्भीय पर्यावरण, समुद्रतटीय क्षेत्रों और अन्तर्देशीय जल संसाधनों आदि सहित अनेक क्षेत्र में किया जाएगा।

एचवाईएसआईएस के समूह में एक वृहद और 8 देशों के 29 लघु उपग्रह शामिल थे। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया (1), कनाडा (1), कोलंबिया (1), फिनलैंड (1), मलेशिया (1), नीदरलैंड्स (1), स्पेन (1) और अमरीका (23) शामिल हैं। इन उपग्रहों का कुल वजन लगभग 261.50 किलोग्राम था। पीएसएलवी की मदद से ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मलेशिया और स्पेन के उपग्रहों को पहली बार प्रक्षेपित किया गया। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और ग्राहकों के बीच वाणिज्यिक समझौते के हिस्से के रूप में इन विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। पीएसएलवी सी-43 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ■

बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को फिर से अपना पूरा समर्थन देते हैं: ब्रिक्स

ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) में 30 नवंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं की अनौपचारिक बैठक का मीडिया वक्तव्य जारी किया गया। वक्तव्य में कहा गया कि हम शांति और स्थिरता वाले विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में प्रतिष्ठापित सिद्धांतों और उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान, लोकतंत्र और कानून के शासन को प्रोत्साहित करने में एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। यहां प्रस्तुत है मीडिया वक्तव्य की मुख्य बातें:

1. हम, ब्राजील के संघीय गणराज्य, रूसी संघ, भारत गणराज्य, चीन के जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार और राज्य के प्रमुख, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं की सालाना अनौपचारिक बैठक के लिए 30 नवंबर 2018 को मिले।

2. हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा एवं वैश्विक आर्थिक-वित्तीय मसलों और साथ ही साथ स्थायी विकास के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। हम शांति और स्थिरता वाले विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में प्रतिष्ठापित सिद्धांतों और उद्देश्यों, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान, लोकतंत्र और कानून के शासन को प्रोत्साहित करने में एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। हम बहुपक्षीयता को मजबूत करने और एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, समान, लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

3. हम ब्रिक्स देशों के खिलाफ किए गए आतंकवादी हमलों समेत अब भी जारी सभी आतंकी हमलों की निंदा करते हैं। हम कहीं भी किए जाने वाले और किसी के भी द्वारा किए जाने वाले आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की भर्त्सना करते हैं। हम मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आतंकवाद के खिलाफ अनुकूल प्रयास करने का अनुरोध करते हैं। हम सभी राष्ट्रों से अनुरोध करते हैं कि वे जोहानसबर्ग घोषणापत्र में पहचाने गए सभी तत्वों को शामिल करते हुए आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाए।

हम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सन्निहित नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को फिर से अपना पूरा समर्थन देते हैं ताकि पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुले और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित किया जा सके। हम डब्ल्यूटीओ के कामकाज में सुधार की दृष्टि से डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ स्पष्ट और परिणाम-आधारित वार्ताओं में जुड़ने को लेकर अपनी आम तत्परता जाहिर करते हैं।

4. हम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सन्निहित नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को फिर से अपना पूरा समर्थन देते हैं ताकि पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुले और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित किया जा सके। हम डब्ल्यूटीओ के कामकाज में सुधार की दृष्टि से डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ स्पष्ट और परिणाम-आधारित वार्ताओं में जुड़ने को लेकर अपनी आम तत्परता जाहिर करते हैं।

5. डब्ल्यूटीओ की जो मूल भावना और नियम हैं वो एकपक्षीय और संरक्षणवादी तौर-तरीकों के खिलाफ जाते हैं। हम सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे डब्ल्यूटीओ के ऐसे असंगत तौर-तरीकों की खिलाफत करे, डब्ल्यूटीओ में शुरू की गई प्रतिबद्धताओं के साथ खड़े रहें और भेदभावपूर्ण व प्रतिबंधक प्रकृति के ऐसे तौर-तरीकों को वापस ले।

6. हम इस दृष्टिकोण से डब्ल्यूटीओ में सुधार की दिशा में कार्य का समर्थन करते हैं कि जिससे मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में उसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके। इस कार्य में डब्ल्यूटीओ के केंद्रीय मूल्यों और मूलभूत सिद्धांतों का संरक्षण होना चाहिए और डब्ल्यूटीओ सदस्यों, खास तौर पर विकासशील सदस्यों के हित प्रतिबिंबित होने चाहिए।

7. डब्ल्यूटीओ के स्वाभाविक कामकाज के लिए इसका विवाद निपटान तंत्र बहुत आवश्यक है। इसके प्रभावी कामकाज से इसके सदस्यों को वो जरूरी आत्मविश्वास मिलेगा जिससे वो डब्ल्यूटीओ में भविष्य की बातचीत से जुड़ सकें। हम इसी कारण से अनुरोध करते हैं कि डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र के स्थिर और प्रभावी कामकाज के लिए मूलभूत पूर्व आवश्यकता के तौर पर अपीलीय संस्था की चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए।

8. हम अन्य सदस्यों के साथ अपना संचार व सहयोग बढ़ाने और संयुक्त व सहयोगी रूप से काम करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता फिर से पुष्ट करते हैं, ताकि डब्ल्यूटीओ को सक्षम किया जा सके कि

वो बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चल सके, समावेशी विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देशों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सके और वैश्विक आर्थिक शासन में एक अर्थपूर्ण भूमिका निभा सके।

9. हम निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाने की जी-20 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता की थीम और काम के भविष्य, विकास के लिए बुनियादी ढांचे और सतत भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा पर फोकस का स्वागत करते हैं।

10. हम विकास के लिए बुनियादी ढांचे के महत्व को पहचानते हैं और वैश्विक बुनियादी ढांचे के बीच अंतर को पाटने में योगदान करने में अपनी प्रतिबद्धता देते हैं, जिसमें स्थायी और आपदारोधी बुनियादी ढांचे के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक समेत राष्ट्रीय और सामूहिक पहलों के माध्यम से संसाधनों के जुटाना शामिल है।

11. हम एक मजबूत वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट की वकालत करते हैं जिसके केंद्र में पर्याप्त संसाधनयुक्त, कोटा आधारित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) हो।

12. हम सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों के लिए उस 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करते हैं जो 2030 तक गरीबी मिटाने के अंतिम लक्ष्य की दिशा में एक संतुलित और समन्वित ढंग से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के तीनों आयामों में समान, समावेशी, खुला, बहुमुखी, नवीनता-संचालित और सतत विकास प्रदान कर सके। हम विकसित देशों से अनुरोध करते हैं कि वे समय पर और पूर्ण ढंग से अपनी ओडीए प्रतिबद्धताओं का सम्मान करे और एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा के अनुसार विकासशील देशों को अतिरिक्त विकास संसाधन मुहैया करवाए।

13. वैश्विक आर्थिक विस्तार जारी है, हालांकि ये कम संतुलित रहा है और इसमें नकारात्मक पक्ष ये रहा है कि जोखिम बढ़े हैं। हम चिंतित हैं कि प्रमुख आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के नीति सामान्यीकरण से जो नकारात्मक परिणाम हुए हैं वो उस अस्थिरता का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे हाल ही में कुछ उभरते हुए बाजारों में देखा गया है। हम सभी अर्थव्यवस्थाओं का आह्वान करते हैं कि वे जी-20 भागीदारी की मूल भावना में अपने नीति संवाद और समन्वय को मजबूत करे, ताकि संभावित जोखिमों को फैलने से रोका जा सके।

14. जहां तक जलवायु परिवर्तन का संबंध है हम आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांतों समेत यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों के अंतर्गत अपनाए गए पैरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए खुद को पुनः प्रतिबद्ध करते हैं और विकसित देशों से अनुरोध करते हैं कि वे विकासशील देशों की शमन और अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उनको वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहयोग प्रदान करें। हम सभी देशों का आह्वान करते हैं कि वे सीओपी-24 के दौरान पैरिस समझौता कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत एक संतुलित नतीजे तक पहुंचे, जिससे पैरिस समझौते के संचालन और कार्यान्वयन को सक्षम किया जा सके। हम हरित जलवायु फंड की पहली सफल और महत्वाकांक्षी पुनः पूर्ति प्रक्रिया संचालित करने की तीव्र आवश्यकता और महत्व पर ज़ोर देते हैं।

15. हम न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर ब्रिक्स भागीदारी (पार्टएनआईआर), ब्रिक्स वेक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म और साओ पाउलो में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अमेरिका के क्षेत्रीय कार्यालय को स्थापित करने समेत दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में अर्थव्यवस्था, शांति, सुरक्षा और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान के क्षेत्रों में ब्रिक्स सहयोग की उपलब्धियों पर अपना संतोष जाहिर करते हैं। हम जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन और पूर्व में हुए शिखर सम्मेलनों में निकले नतीजों को पूर्ण रूप से लागू करने के अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करते हैं। ■

ब्रिटेन की अदालत द्वारा विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश

कानून से बच कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को 10 दिसंबर को ब्रिटेन की अदालत ने उसे भारत के हवाले करने की अनुमति दे दी। इस समय ब्रिटेन में रह रहे माल्या पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से जमानत पर है। उस पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये बकाया है और माल्या पर किंगफिशर एयरलाइन के लिए लिए बैंकों से लिए गए कर्ज में हेराफेरी और और मनी लांडरिंग का आरोप है। यह एयरलाइन बंद हो चुकी है।

ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट जज एम्मा आबुथनॉट माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी, ताकि उनके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। माल्या को भारत को सौंपने की अर्जी को माल्या ने चुनौती दी थी। यह मामला पिछले साल चार दिसंबर को मजिस्ट्रेट अदालत में शुरू हुआ था। इस मामले की सुनवाई के लिए शुरू में सात दिन रखे गए थे, लेकिन सुनवाई इससे कहीं अधिक चली। ■

भारत के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है नीली अर्थव्यवस्था: नितिन गडकरी

नौवहन, सड़क यातायात एवं राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत 'इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन (आईओआरए)' की रूपरेखा के जरिये नीली अर्थव्यवस्था को वहनीय, समावेशी और जन आधारित तरीके से प्रोत्साहित करने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है और हमारा 95 प्रतिशत से अधिक का कारोबार समुद्र के जरिये होता है। श्री गडकरी 28 नवंबर को नैरोबी में वहनीय नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन में बोल रहे थे।

भारत द्वारा सामुद्रिक संसाधनों के विकास पर दिए जाने वाले महत्व का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस संबंध में हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रतिपादित 'सागर' (सभी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और विकास) की धारणा का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ नीला चक्र नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नौवहन मंत्रालय इस क्षमता का भरपूर उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री गडकरी ने भारत के महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम का भी उल्लेख किया और बताया कि इस कार्यक्रम से भारत में समुद्र के जरिये सामान के आवागमन तथा बंदरगाह के विकास में क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 600 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें 2020 तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश होगा। कार्यक्रम के तहत तटीय आर्थिक जोन विकसित करने के लिए प्रत्येक स्थल के संबंध में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्रस्तावित है।

श्री गडकरी ने केन्या के यातायात, अवसंरचना, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री जेम्स वायनायना मचारिया के साथ भी बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान जहाज निर्माण, तटरक्षक के लिए जहाज उपलब्ध कराने तथा अन्य क्षेत्रों में भारत के सहयोग की पेशकश की।

श्री गडकरी ने भारत में विकसित होने वाली इलेक्ट्रिक कारों और वाहनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके लिए केन्या में बाजार उपलब्ध हो सकता है। केन्या के मंत्री ने केन्या में जहाज निर्माण शुरू करने के लिए भारत से सहयोग की अपेक्षा की।

उन्होंने सुझाव दिया कि द्विपक्षीय सहयोग को नीली अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को दुपहिया वाहनों के निर्माण में महारत हासिल है और केन्या तथा अन्य अफ्रीकी देशों में उसके लिए बड़ा बाजार मौजूद है। केन्या के मंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियों के लिए यहां अच्छा निवेश अवसर मौजूद है। ■

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव कर मिसाल कायम की : धर्मेन्द्र प्रधान

केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 30 नवंबर को कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव करके एक मिसाल कायम की है। सीआईआई द्वारा आयोजित 15वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को नई दिल्ली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सस्ती, सुगम्य और लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी व्यवस्था के बाहर प्रतिभा, ऊर्जा और संसाधनों को बाहर निकालकर एक उद्यमिता मॉडल तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जिसका लोकप्रिय नाम मोदी केयर है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है जिसे राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है और जो देश की लगभग आदि आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। श्री प्रधान ने कहा कि अधिक डॉक्टर, अर्ध चिकित्सक, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा आदि प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि भारत विदेशी मरीजों खासतौर से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के मरीजों का प्रिय स्थल बन गया है।

श्री प्रधान ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कुशल मानव शक्ति प्रदान करने के लिए जापान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ औपचारिक समझौते किए गए हैं, क्योंकि भारतीय मानव शक्ति में संवेदनशीलता, सहानुभूति और जिम्मदारी का भाव है।

श्री प्रधान ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सेवा परिषद प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। सरकार ने सहायक और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सांविधिक संगठन स्थापित करने की मांग को पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय दवा उद्योग पहले से ही दुनियाभर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। श्री प्रधान ने कहा कि भारत सस्ते स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए एक प्रयोगशाला बन सकता है। उन्होंने सभी साझेदारों से कहा कि वे इन प्रयासों में योगदान दें। ■

सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन जारी

विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच किसी भी देश में जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए सरकार 31 मार्च, 2019 तक सभी के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य के तहत कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर लिए गए हैं और वर्ष 2018 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 28 अप्रैल, 2018 को हर गांव में बिजली के लिए ऐतिहासिक रहा है। अब सौभाग्य योजना के तहत हर घर के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 9 राज्य पहले से ही 100% घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। ये लक्ष्य भी अपनी समय सीमा से पहले हासिल किए जाएंगे।

विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण समेत बिजली क्षेत्र को सुधारने और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें न केवल क्षमता वृद्धि में उपलब्धियां शामिल हैं, बल्कि ऊर्जा दक्षता में वृद्धि और उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ने जैसे प्राप्ति, एश ट्रैक इत्यादि लॉन्च करके महत्वपूर्ण सुधार भी किए जा रहे हैं।

बिजली मंत्रालय की वार्षिक उपलब्धियां निम्न हैं:

सौभाग्य

- सितंबर, 2017 में यह योजना सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई।
- गांव के स्तर पर शिविर आयोजित किए गए, जिसमें न्यूनतम दस्तावेज आवश्यक हैं।
- ग्राम स्वराज अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
- 11 अक्टूबर, 2017 से 2.1 करोड़ से ज्यादा परिवार विद्युतीकृत हुए।
- 9 राज्यों मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगालने सौभाग्य योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण में 100% संतृप्ति हासिल की है।
- इस प्रकार देश में कुल 16 राज्यों में अब 100% घरेलू विद्युतीकरण है।
- महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि जैसे कई राज्यों को गैर-विद्युतीकृत घर बाकी रह गए हैं और इनके किसी भी समय विद्युतीकृत होने की उम्मीद है।

- राष्ट्र को 31 दिसंबर, 2018 तक 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने की उम्मीद है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीजीजीवाई)

- 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ
- इस पर 75,893 करोड़ रुपये खर्च हुए
- 2,58,870 किमी एचटी और एलटी लाइनें बिछाई गईं

जनरेशन क्षमता

- अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2018 तक 1,07,000 मेगावॉट उत्पादन क्षमता बढ़ी है।
- अखिल भारतीय स्तर पर जनरेशन क्षमता 39.2% बढ़कर 31.10.2018 तक 3,46,048 मेगावाट हो गई है, जो 31.3.2014 तक 2,48,554 मेगावॉट थी।
- भारत बिजली के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2017-18 में 7203 एमयू नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को आपूर्ति की गई और 468 एमयू चालू वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018 तक) में आपूर्ति की गई।
- वित्त वर्ष 2013-14 में ऊर्जा घाटा 4.2% से घटकर वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018 तक) में 0.6% हो गया। वित्त वर्ष 2013-14 में मुख्य घाटा भी घटकर वित्त वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018 तक) में 0.8% हो गया।
- 2013-14 में इसी अवधि के दौरान 1,29,1515 मेगावाट से मुख्य मांग चालू वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2018) के दौरान 35.2% बढ़कर 1,75,528 मेगावाट पहुंच गई।
- 2013-14 में इसी अवधि के दौरान 565.698 बीयू से चालू वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2018) के दौरान ऊर्जा उपलब्धता में भी 35.2% बढ़कर 764.627 बीयू हो गई है।

वर्षांत समीक्षा 2018 की मुख्य बातें

- **सौभाग्य के तहत 2 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन जारी किए गए**
- **डीडीयूजीजेवाई के तहत 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ**
- **सौभाग्य योजना के तहत 9 राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण हुआ**
- **कुल 16 राज्यों में अब 100% घरों का विद्युतीकरण हो चुका है**
- **ऊर्जा घाटा लगभग शून्य हो गया और भारत नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को बिजली के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है**
- **उजाला योजना के तहत 31.68 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए और 74.7 9 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित किए गए हैं**
- **"बिजली" प्राप्त करने के मामले में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूनिंग बिजनेस में भारत की रैंक बढ़कर 2018 में 24 हो गई, जबकि 2014 में यह 137 थी**

एक ग्रिड, एक राष्ट्र (अक्टूबर, 2018 तक उपलब्धियां)

- 2014-15 से 2018-19 तक 1,11,433 सीकेएम संचरण ग्रिड का विस्तार हुआ (वित्त वर्ष 2018-19 में 11,799 सीकेएम जोड़ा गया)।
- 2014-15 से 2018-19 तक 3,38,202 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन क्षमता वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2018-19 में 41,790 एमवीए जोड़ा गया)।
- 2014-15 से 2018-19 तक 26 परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 48,426 करोड़ रुपये दिए गए।
- वित्त वर्ष 2010-14 में 16,000 वाली अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण क्षमता बढ़कर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 54,700 मेगावाट गई, जबकि 2018-19 (वित्त वर्ष 2018-19 में यह 4,200 मेगावाट) हो गई।

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

- इस पर 65,424 करोड़ रुपये का परिव्यय हुआ।
- 1378 कस्बे आईटी सक्षम
- 1,30,348 किलोमीटर में से 43,449 किमी एचटी और एलटी लाइन स्थापित कर दी गई
- कुल 58,145 में से 28,193 वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए गए

उदय

- दो साल के भीतर उदय के तहत डिस्कॉम द्वारा 34,000 करोड़ रुपये से ज्यादा ब्याज लागत बचाई गई।
- संचालन के दो वर्षों के भीतर 22 राज्यों में एटी और सी घाटे में कमी। वित्त वर्ष 2018 में एटी एंड सी घाटे में 18.76% की कमी आई है, जबकि यह वित्त वर्ष 2016 में 20.77% थी। उदय के दो साल के संचालन के भीतर राजस्व अंतर 72 प्रतिशत बढ़ गया। वित्त वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर एसीएस-एआरआर अंतराल 17 पैसे प्रति इकाई है, जबकि वित्त वर्ष 2016 में यह 60 पैसे प्रति इकाई थी।
- "बिजली" प्राप्त करने के मामले में विश्व बैंक की इज ऑफ डूनिंग बिजनेस में भारत की रैंक बढ़कर 2018 में 24 हो गई, जबकि 2014 में यह 137 थी। ■

2017-18 में 28.48 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार के प्रयासों से कृषि क्षेत्र में काफी अधिक प्रगति हुई है। श्री सिंह ने यह बात 29 नवंबर को रांची में दो दिवसीय वैश्विक कृषि और खाद्य सम्मेलन 2018 में उद्घाटन भाषण में कही।

उन्होंने बताया कि देश में 2017-18 में (चौथा पूर्व अनुमान) 28.48 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ, जबकि 2010-14 में 25.56 करोड़ टन औसत उत्पादन हुआ था। 2017-18 में दाल का 25.23 मिलियन टन (चौथा पूर्व अनुमान) उत्पादन हुआ। इस तरह 2010-14 के 18.01 मिलियन टन की तुलना में दाल उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बागवानी फसलों में रिकॉर्ड 15.79 प्रतिशत वृद्धि हुई, नीली क्रांति के अंतर्गत मछली उत्पादन 26.86 प्रतिशत बढ़ा और पशुपालन तथा दूध उत्पादन में 23.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- **देश में 2017-18 में (चौथा पूर्व अनुमान) 28.48 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ, जबकि 2010-14 में 25.56 करोड़ टन औसत उत्पादन हुआ था।**
- **कृषि लागत कम करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया के उपयोग तथा प्रति बूंद अधिक फसल से जुड़ी योजनाओं पर बल दिया जा रहा है।**
- **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से लगभग 5.5 लाख लोगों के लिए रोजगार अवसर तैयार किये जा रहे हैं।**

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि उत्पादन लागत घटाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया के इस्तेमाल और प्रति बूंद अधिक फसल से संबंधित योजनाएं लक्षित रूप में लागू की जा रही हैं। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 2014-15 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) प्रारंभ की गई और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र मिशन ऑर्गेनिक वेल्यू चेंज डवलपमेंट (एमओवीसीडी-एनईआर) प्रारंभ किया गया।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई नैम) प्रारंभ किया गया है, ताकि एक देश एक बाजार की ओर बढ़ते हुए किसानों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। मार्च 2018 तक ई नैम के साथ 585 मंडियों को जोड़ने का काम किया गया। इसके अतिरिक्त खरीफ फसल 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफडीवाई) शुरू की गई, ताकि आपदाओं के कारण कृषि जोखिम पर काबू पाया जा सके।

श्री सिंह ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि में गुणवत्ता को प्रोत्साहित कर रही है। 6 हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रारंभ की गई है। खादय प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि प्रसंस्करण कलस्टरों के फावर्ड और बेकवर्ड लिंकेज विकसित किये जा रहे हैं। लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और लगभग 5.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार किये जा रहे हैं। ■

अक्टूबर, 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 4.8%

सीमेंट उत्पादन 18.4 प्रतिशत बढ़ा

आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अक्टूबर, 2018 में 134.8 अंक रहा, जो अक्टूबर, 2017 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 4.8 प्रतिशत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, अक्टूबर 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2018-19 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही।

सीमेंट : अक्टूबर, 2018 के दौरान सीमेंट उत्पादन (भारांकः 5.37%) अक्टूबर, 2017 के मुकाबले 18.4 प्रतिशत ज्यादा रहा। अप्रैल-अक्टूबर, 2018-19 के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.0 प्रतिशत अधिक रहा।

बिजली : अक्टूबर, 2018 के दौरान बिजली उत्पादन (भारांकः 19.85%) में अक्टूबर, 2017 के मुकाबले 11.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अप्रैल- अक्टूबर, 2018-19 में बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 6.9 प्रतिशत अधिक रहा।

कोयला : अक्टूबर, 2018 में कोयला उत्पादन (भारांकः 10.33%) अक्टूबर, 2017 के मुकाबले 10.6 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल- अक्टूबर, 2018-19 में कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक रही।

कच्चा तेल : अक्टूबर, 2018 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन (भारांकः 8.98%) अक्टूबर, 2017 की तुलना में 5.0 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल- अक्टूबर, 2018-19 में कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.6 प्रतिशत कम रहा। ■

लोकतंत्र का गला घोंट रही है ममता सरकार : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 7 दिसंबर को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये पर जमकर प्रहार किया।

श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोक सभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी के संगठन विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में यात्राओं का आयोजन किया था जो इसी महीने 7, 9 और 14 दिसंबर को शुरू होने वाले थे। इसके लिए हमने विगत 29 अक्टूबर को पहली बार राज्य के गृह सचिव और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र लिख कर परमिशन की मांग की थी। परमिशन न मिलने पर 5, 12 और 20 नवंबर को फिर से रिमाइंडर भेजे गए। राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 14, 20 और 23 नवंबर को परमिशन के लिए रिमाइंडर्स भेजे गए, लेकिन हमें यात्रा की परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार और सत्ता का दुरुपयोग करके पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक और राजनीतिक यात्राओं का दमन करने की जो परंपरा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपना रही हैं, यह घोर अलोकतांत्रिक है और लोकतंत्र का गला घोंटने वाली घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी के 7 साल के कुशासन के खिलाफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के हर जिले में, हर मंडल में आवाज उठाई है और इससे राज्य में जो जनजागृति आ रही है, इससे ममता बनर्जी डरी हुई है। ममता बनर्जी के जहन में इस बात का डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ये तीनों यात्राएं पश्चिम बंगाल की हर विधान सभा, हर मंडल से होते हुए गुजरती है और जब इन यात्राओं का कोलकाता में समापन होगा, तब पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की नींव डल चुकी होगी, इसलिए ममता बनर्जी सरकार ने इन यात्राओं को रोकने की साजिश रची।

श्री शाह ने कहा कि इसके पूर्व जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें इतनी हिंसा हुई जितनी कभी भी पंचायत चुनावों में पश्चिम बंगाल में पहले नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को "जोड़ जाड़, बूथ तार" का नारा दिया था जिसका मतलब है जिसके हाथ में जोर है, बूथ उसी के कब्जे में रहना चाहिए। क्या लोकतंत्र में इस प्रकार के नारों से लोकतंत्र की कभी भलाई हो सकती है? उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, हमारे 1341 कार्यकर्ता जख्मी हुए और कुल मिलाकर पंचायत चुनावों में पश्चिम बंगाल में 65 से भी अधिक राजनीतिक हत्याएं हुई। उन्होंने कहा कि तृणमूल समर्थित कार्यकर्ताओं के हमले में शहीद हमारे तीन कार्यकर्ताओं त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार और जगन्नाथ टुंडू की निर्मम हत्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नामजद हैं। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं कि इन तीनों मामलों का वर्तमान स्टेटस क्या है? इन तीनों में मामलों में क्या प्रगति हुई है? उन्होंने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ता और राज्य की पुलिस दोनों इकठ्ठा होकर राजनीतिक हत्याओं को शह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में 34% सीटों पर कोई चुनाव ही नहीं हुए, लगभग दो करोड़ मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिला, क्योंकि तृणमूल कार्यकर्ताओं के तांडव के कारण

प्रत्याशी अपना नामांकन तक दाखिल नहीं कर पाए। स्थिति तो इस कदर खराब हो गई कि हाईकोर्ट को यह निर्देश जारी करना पड़ा कि प्रत्याशी व्हाट्सअप पर अपना पर्चा डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सब के बावजूद हम पंचायत चुनावों में सात हजार से ज्यादा सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर काबिज हुए। उन्होंने कहा कि हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से डर कर उन्होंने इन यात्राओं को परमिशन न देकर रोकने का कार्य किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां तक क़ानून-व्यवस्था का सवाल है- शिक्षा, खनन, बंदरगाह, हर जगह माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्री इन माफियाओं को पनाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आजकल हर जगह जगाई-मधाई दिखाई दे रहे हैं। ज्ञात हो कि जगाई-मधाई ने भगवान् चैतन्य महाप्रभु पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या घुसपैठ की बात हो या फिर अन्य घुसपैठ की, हर तरह के घुसपैठ को सरकारी तंत्र का आशीर्वाद प्राप्त है। 2014 के NCRB डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल की क्राइम रेट अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे है। यह पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति की द्योतक है। राजनीतिक हत्यायों में पश्चिम बंगाल विगत कई वर्षों से अग्रिम राज्यों में रहा है। मंदिरों से मूर्तियों की चोरी के सबसे अधिक मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज किये गए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने वाली संस्थाओं पर नकेल कसने की तृणमूल सरकार की न तो मंशा है और न ही नकेल कसने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के कारण राज्य का पूरा प्रशासन लचर हो चुका है। स्थानीय प्रशासन भी वोट बैंक की राजनीति करने में लगी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को तो वोट बैंक की राजनीति करते हमने कांग्रेस के जमाने से देखा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब वोट बैंक की राजनीति करे तो किस प्रकार के खराब परिणाम आ सकते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण पश्चिम बंगाल है।

जो पश्चिम बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चन्द्र चटर्जी और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानुभावों की धरती है, जहां कभी रवींद्र संगीत गूंजा करता था, आज वहां बम धमाकों की आवाज सुनाई देती है। बम धमाकों की आवाज में रवींद्र संगीत न जाने कहां गुम हो गया है। बड़ी वेदना के साथ यह कहना चाहता हूं कि हम पश्चिम बंगाल की यह स्थिति बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और बदलाव लाकर रहेंगे।

कई उदाहरण देते हुए श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई सारी बम और आर्म्स फैक्ट्रियां पकड़ी गई, लेकिन ये फैक्ट्रियां पुलिस की इनिशिएटिव के कारण नहीं बल्कि इन फैक्ट्रियों में अचानक हुए धमाकों के कारण इसका पकड़ा जाना मुमकिन हो सका। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन, रामनवमी, सरस्वती पूजा, इन सब त्यौहारों पर वोट बैंक की राजनीति करके प्रतिबंध लगाना और धार्मिक अनुष्ठानों में अवरोध उत्पन्न करना पश्चिम बंगाल में परंपरा बन चुकी है। चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, मूर्ति विसर्जन करना हो, कोई यात्रा निकालनी हो, कोई सभा करनी हो तो पश्चिम बंगाल में आपको परमिशन के लिए न्यायालय जाना पड़ता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन तो आपको परमिशन देगा नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले में भी पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी गंभीर है। मानव तस्करी के 44% मामले पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल की कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कितनी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी दयनीय है। मेडिकल में दाखिले के लिए 15 लाख, तो कॉलेजों में भी दाखिले के लिए 50 से 60 हजार रुपये तक देने पड़ते हैं। हर एडमिशन का रेट फिक्स्ड है, यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की इन यात्राओं को रोककर पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं का दमन नहीं कर सकती, इसके ठीक विपरीत, जनता का गुस्सा आपके ऊपर और बढ़ेगा ही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार के दमन चक्र से नहीं डरते। हम पश्चिम बंगाल में सुशासन और वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जब 2019 का लोक सभा चुनाव होगा तो पश्चिम बंगाल की अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक इन तीनों यात्राओं का सवाल है, तो ये तीनों यात्राएं निश्चित होगी। ममता बनर्जी जितना जोर लगाना चाहें, लगा लें, लेकिन ये यात्राएं होकर रहेगी। मैं स्वयं इन यात्राओं की शुरुआत करने पश्चिम बंगाल जाऊंगा। ये यात्राएं पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में जायेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तृणमूल सरकार के गैर-लोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ जनता को जागृत करने का काम करेगी।

श्री शाह ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चन्द्र चटर्जी और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानुभावों की धरती है, जहां कभी रवींद्र संगीत गूंजा करता था, आज वहां बम धमाकों की आवाज सुनाई देती है। बम धमाकों की आवाज में रवींद्र संगीत न जाने कहां गुम हो गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी वेदना के साथ यह कहना चाहता हूं कि हम पश्चिम बंगाल की यह स्थिति बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और बदलाव लाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के डर को समझते हैं, लेकिन उनका डर दूर करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी सरकार को हटा कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का निश्चय कर लिया है और हम जनता के आशीर्वाद के लिए उनके बीच जरूर जायेंगे। ■

सौभाग्य योजना के अंतर्गत 8 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत 8 राज्यों- मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल- ने 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब देश के कुल 15 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो गया है।

यह बात केन्द्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर के सिंह ने 29 नवंबर को नई दिल्ली में राज्यों तथा राज्यों की विद्युत कंपनियों के साथ समीक्षा, नियोजन और निगरानी बैठक के बाद बताई। गौरतलब है कि सौभाग्य योजना सितम्बर 2017 मे लांच की गई थी। इसका उद्देश्य देश में शेष बचे घरों तक बिजली पहुंचाना है। श्री आर के सिंह ने बताया कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत अब तक 2.1 करोड़ कनेक्शन जारी किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विद्युतीकरण से वंचित घर कम संख्या में बचे हैं और आशा है कि सभी घरों का विद्युतीकरण हो जायेगा। उन्होंने बताया कि विदयुतीकरण की वर्तमान गति के मुताबिक देश के सभी 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसम्बर 2018 तक पूरा हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि देश में 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण से सभी के

लिए 24x7 बिजली देने का रिकॉर्ड कायम होगा। सरकार 31 मार्च, 2019 तक सभी के लिए 24x7 बिजली पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है।

100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण वाले राज्यों में कोई घर वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बारे में सभी क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलायें, ताकि किसी वंचित हुए घर को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत लाभ मिल सके। ■

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल का प्रत्यर्पण

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को 4 दिसंबर की रात यूएई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। यह भारतीय जांच एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है।

भारत ने मिशेल के प्रत्यर्पण के लिए दुबई से 2017 में औपचारिक अनुरोध किया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के आधार पर तमाम सबूत और दस्तावेज यूएई सरकार को सौंपे गए थे। कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल करने के बाद जांच एजेंसियों ने इंटरपोल से संपर्क साधा था।

जांच एजेंसियों के अनुसार मिशेल सौदे में दी गई रिश्वत के मामले में अहम कड़ी है। ईडी ने मिशेल के खिलाफ जून 2016 में दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा था कि मिशेल ने दुबई में अपनी एक फर्म के जरिये दिल्ली में अपनी एक मीडिया फर्म तक घूस पहुंचाई। इस फर्म में दो भारतीय भागीदार भी थे। रिश्वत की यह रकम अधिकारियों

और सौदे से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचाई गई। अगस्ता वेस्टलैंड ने दिखाया कि यह राशि सौदे से जुड़े कार्यों को पूरा करने की एवज में दी गई थी। ■

यह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृति अमर रहेगी: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को 'मन की बात' कार्यक्रम की 50वीं कड़ी के दौरान कहा कि जब मैंने मई 2014 में एक 'प्रधान-सेवक' के रूप में कार्यभार संभाला तो मेरे मन में इच्छा थी कि देश की एकता, हमारे भव्य इतिहास, उसका शौर्य, भारत की विविधताएं, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारे समाज के रग-रग में समायी हुई अच्छाइयां, लोगों का पुरुषार्थ, जज़्बा, त्याग, तपस्या इन सारी बातों को भारत की यह कहानी जन-जन तक पहुंचनी चाहिये।

श्री मोदी ने कहा कि देश के दूर-सुदूर गावों से लेकर मेट्रो सिटीज तक किसानों से लेकर के युवा प्रोफेशनल्स तक और बस उसी में से ये 'मन की बात' की यात्रा प्रारंभ हो गयी। हर महीने लाखों की संख्या में पत्रों को पढ़ते, फ़ोन कॉल्स सुनते, एप्प और MyGov पर कमेंट देखते और इन सबको एक सूत्र में पिरोकर के, हल्की-फुल्की बातें करते-करते 50 एपिसोड का एक सफ़र हम सबने मिलकर के तय कर ली है। हाल ही में आकाशवाणी ने 'मन की बात' पर सर्वे भी कराया। मैंने उनमें से कुछ ऐसे फीडबैक को देखा जो काफी दिलचस्प हैं। जिन लोगों के बीच सर्वे किया गया है, उनमें से औसतन 70% नियमित रूप से 'मन की बात' सुनने वाले लोग हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर लोगों को लगता है कि 'मन की बात' का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने समाज में पॉजिटिविटी की भावना बढ़ायी है। 'मन की बात' के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन-आन्दोलनों को बढ़ावा मिला है। # इंडियापॉजिटिव को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई है। ये हमारे देशवासियों के मन में बसी पॉजिटिविटी की भावना की, सकारात्मकता की भावना की भी झलक है। लोगों ने अपना ये अनुभव भी शेयर किया है कि 'मन की बात' से स्वेच्छा से कुछ करने की भावना बढ़ी है। एक ऐसा बदलाव आया है जिसमें समाज की सेवा के लिए लोग बढ़चढ़ करके आगे आ रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे यह देखकर के खुशी हुई कि 'मन की बात' के कारण रेडियो, और अधिक लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन यह केवल रेडियो ही नहीं है जिसके माध्यम से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लोग टी.वी., एफ़.एम. रेडियो, मोबाइल, इन्टरनेट, फ़ेसबुक लाइव, और पेरिस्कोप के साथ-साथ NarendraModiApp के माध्यम से भी 'मन की बात' में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी आएगा और चला जाएगा, लेकिन यह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृति अमर रहेगी। 130 करोड़ देशवासियों की छोटी-छोटी यह कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी। इस देश को नयी प्रेरणा में उत्साह से नयी ऊंचाइयों पर लेती जाती रहेंगी। मैं भी कभी-कभी पीछे मुड़कर के देखता हूं तो मुझे भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कोई देश के किसी कोने से पत्र लिखकर कहता है - हमें छोटे दुकानदारों, ऑटो चलाने वालों, सब्जी बेचने वालों ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मोल-भाव नहीं करना चाहिये। मैं पत्र पढता हूं, ऐसा ही भाव कभी किसी और पत्र में आया हो उसको साथ गूंथ लेता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि कभी-कभी 'मन की बात' का मजाक भी उड़ता है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही 130 करोड़ देशवासी बसे रहते हैं। उनका मन मेरा मन है। 'मन की बात' सरकारी बात नहीं है - यह समाज की बात है। 'मन की बात' एक महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल-प्राण राजनीति नहीं है, भारत का मूल-प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल-प्राण समाजनीति है और समाज-शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं उनमें से एक पहलू राजनीति भी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी-कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए जन-सामान्य की प्रतिभाएं पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, यह हम सबका एक सामूहिक दायित्व है और 'मन की बात' इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कल 'संविधान दिवस' है। उन महान विभूतियों को याद करने का दिन जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। 26 नवम्बर, 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया

था। संविधान ड्रॉफ्ट करने के इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 2 वर्ष, 11 महीने और 17 दिन लगे। कल्पना कीजिये 3 वर्ष के भीतर ही इन महान विभूतियों ने हमें इतना व्यापक और विस्तृत संविधान दिया।

श्री मोदी ने कहा कि संविधान सभा देश की महान प्रतिभाओं का संगम थी, उनमें से हर कोई अपने देश को एक ऐसा संविधान देने के लिए प्रतिबद्ध था, जिससे भारत के लोग सशक्त हों, ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति भी समर्थ बने।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में खास बात यही है कि अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नागरिक के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे ले जाएगा। अगर हम दूसरों के अधिकार का सम्मान करेंगे, तो हमारे अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जायेगी और इसी तरह अगर हम संविधान में दिए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो भी हमारे अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जायेगी।

उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है 2010 में जब भारत के गणतंत्र को 60 साल हुए थे, तब गुजरात में हमने हाथी पर रखकर संविधान की शोभा-यात्रा निकाली थी। युवाओं में संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें संविधान के पहलुओं से जोड़ने के लिए यह एक यादगार प्रसंग था। वर्ष 2020 में एक गणतंत्र के रूप में हम 70 साल पूरे करेंगे और 2022 में हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जायेंगे। ■

राफेल सौदे में नहीं मिला अनियमितता का कोई सबूत: उच्चतम न्यायालय

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं

उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के मामले में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति श्री केएम जोसेफ की पीठ ने 14 दिसंबर को कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। ऑफसेट साझेदार के मामले पर तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी भी निजी फर्म को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

अदालत की निगरानी में राफेल सौदे की जांच कराने की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी।

राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुये इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का सीबीआई को निर्देश देने और न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच के अनुरोध के साथ ये याचिकायें दायर की गयी थीं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश इन विमानों के बगैर नहीं रह सकता है। तीन सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश श्री गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

पीठ ने कहा कि खरीदी, कीमत और ऑफसेट साझेदार के मामले

में हस्तक्षेप के लिए उसके पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि भारतीय वायुसेना को चौथी और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत है।

पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की खरीद से जुड़े सभी पहलुओं पर स्पष्टीकरण दिया है। न्यायालय ने कहा कि सितंबर 2016 में राफेल सौदे को जब अंतिम रूप दिया जा रहा था, उस वक्त किसी ने इसकी खरीद पर सवाल नहीं उठाया।

उन्होंने कहा कि राफेल सौदे पर सवाल उस वक्त उठे जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने बयान दिया, यह न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि वह सरकार को 126 या 36 विमान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में आयोजित गुरू नानक जयंती समारोह में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री ज्यां क्लोद जुंके और यूरोपीय परिषद् के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट हाउस काम्प्लेक्स में बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. बीआर अम्बेडकर के 63वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान जी-20 देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

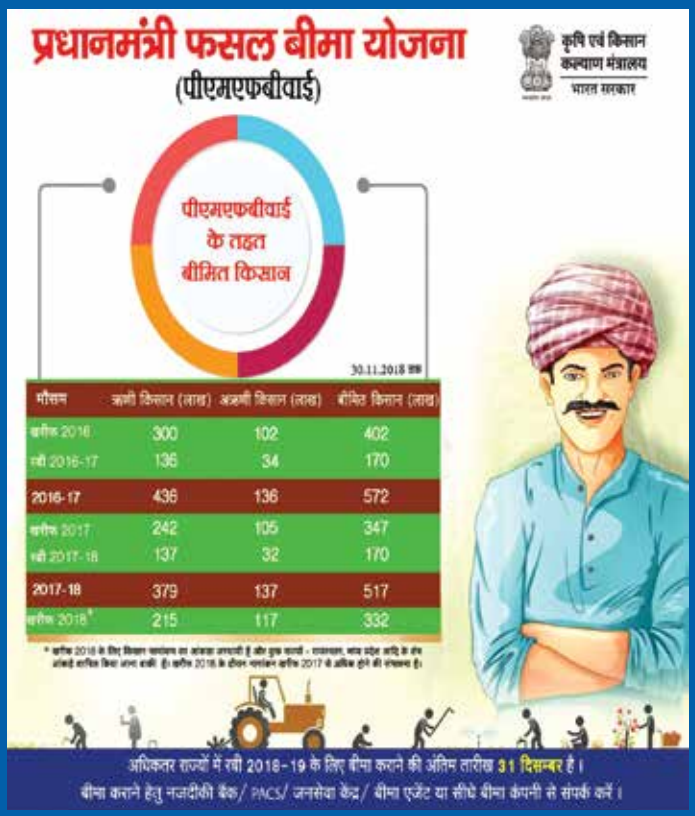

मौसम	ऋणी किसान (लाख)	अऋणी किसान (लाख)	बीमित किसान (लाख)
खरीफ 2016	300	102	402
रबी 2016-17	136	34	170
2016-17	436	136	572
खरीफ 2017	242	105	347
रबी 2017-18	137	32	170
2017-18	379	137	517
खरीफ 2018*	215	117	332